

## वैदेशिक क्षेत्र

वैदेशिक पक्ष पर भारत की समष्टि आर्थिक स्थिति स्थिर रही है। यद्यपि भारत का चालू खाता घाटा वर्ष 2017-18 में जीडीपी का 1.8 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 2.4 प्रतिशत होने का अनुमान है; यह युक्ति संगत स्तर के भीतर है। यह बढ़ता हुआ चालू खाता घाटा दो वर्षों में व्यापार घाटे की जीडीपी के 6.0 प्रतिशत से 6.7 प्रतिशत तक अवनति के कारण हुआ है। 2018-19 की चौथी तिमाही में कच्चे तेल में उछाल एवं वस्तु निर्यातों की वृद्धि में तीव्र गिरावट, व्यापार घाटे में अवनति के लिए उत्तरदायी रही है। धन-प्रेषण की वृद्धि में बढ़ोत्तरी ने कुछ हद तक चालू खाता घाटे की अवनति नियंत्रित रखी है। चालू खाता घाटा को वित्तपोषित करने में, कुल देनदारियों एवं जीडीपी का अनुपात, ऋण और गैर ऋण घटक दोनों को मिलाकर, 2015 के 43 प्रतिशत से घटकर 2018 में लगभग 38 प्रतिशत मापी जा रही है। कुल देनदारियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का हिस्सा बढ़ा है जबकि निवल पोर्टफोलियो निवेश का हिस्सा घटा है जो कि चालू खाता घाटा वित्त पोषण के बढ़ते स्थायी साधनों के स्वरूप को प्रदर्शित कर रहा है। कुल मिलाकर, हाल ही में यद्यपि जीडीपी के अनुपात में चालू खाता घाटा बढ़ना शुरू हो गया है, विदेशी ऋणग्रस्तता कम हो रही है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आराम से 400 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का बना रहा। भारतीय रुपये ने 2017-18 में 65-68 प्रति अमरीकी डालर के बीच में कारोबार किया था परंतु 2018-19 में यह 70-74 के बीच तक गिर गया था। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर भी 2018-19 में गिरी थी जिसने भारत के निर्यात को और अधिक प्रतियोगितात्मक बना दिया। व्यापार के संबंध में आय, एक मापक जो कि आयात की क्रय शक्ति मापती है, आरोही प्रवृत्ति पर रही, संभवतः इसलिए क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों की वृद्धि भारत की निर्यात कीमतों से अभी तक अधिक नहीं हो पाई थी। वर्ष 2018-19 में विनिमय दर पिछले वर्ष की तुलना में अधिक अस्थिर रही जिसका मुख्य कारण कच्चे तेल के मूल्यों में उतार-चढ़ाव रहा, न कि यह उतार-चढ़ाव निवल पोर्टफोलियो प्रवाहों के कारण रहा। भारत की आयात एवं निर्यात टोकरी का संघटन 2017-18 की अपेक्षा 2018-19 में कमोवेश अपरिवर्तित बना रहा। पेट्रोलियम पदार्थों, बहुमूल्य रत्न, सूत्र विन्यासित औषधियां, सोने एवं अन्य बहुमूल्य धातुएं शीर्ष निर्यात वस्तुएं बनीं रही हैं। कच्चा पेट्रोल तेल, मोती, बहुमूल्य, अर्धबहुमूल्य पत्थर तथा सोना शीर्ष आयात वस्तु बनी रही। भारत के मुख्य व्यापार भागीदार अमरीका, चीन, हांगकांग, यूई तथा सऊदी अरब बने रहे।

### 1. वैश्विक आर्थिक परिवेश

#### व्यापार संरक्षणवाद को बढ़ावा तथा वैश्विक उत्पादन में कमी

6.1 वर्ष 2018-19 अधोगामी वक्रपथ पर विश्व उत्पादन में वृद्धि के साथ समाप्त हुआ है। वर्ल्ड इकानोमिक आउटलुक (डब्ल्यू ई ओ) ने अपने अप्रैल 2019 के प्रकाशन में 2019 में 3.3 प्रतिशत विश्व उत्पादन में वृद्धि अनुमानित की है जो कि 2018 में प्राप्त की गई 3.6 प्रतिशत से कम बढ़ी हुई है। अमरीका

चीन व्यापार तनाव वैश्विक मंदी के पीछे कारणों में से एक-एक के रूप में वर्णित किया है जिसने भारत सहित अन्य अर्थव्यवस्थाओं को निर्यात की प्रणाली के जरिए फैला दिया है। 2019 की शुरुआत से ही वैश्विक मंदी ने उन्नत राष्ट्रों को उनका उदार मौद्रिक नीति स्वरूप से दृढ़ बनाये रखा। इसने उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को उनकी मुद्राएं मजबूत बनाने तथा आयात सस्ता करने में पोर्टफोलियो निवेश को बढ़ाया है।

6.2 डब्ल्यू ई ओ इसके आगे यह बताता है कि विश्व

में बढ़ रहा व्यापार संरक्षणवाद जिसमें सबसे अधिक अमरीका-चीन व्यापार तनाव का हाल ही में अविर्भाव है, ने मशीनरी एवं उपस्कर के न्यून सापेक्ष मूल्य जो कि वर्षों से गिरे हैं पर जोखिम डाला है। अंशतः व्यापार अखण्डता बढ़ने के कारण तथा विकासशील देशों में वास्तविक निवेश दर में वृद्धि को सहायता की है। डब्ल्यू ई ओ ने यह भी स्पष्ट किया है कि व्यापार संरक्षणवाद केवल द्विपक्षीय व्यापार असंतुलन को एक देश से अन्य देश की ओर ले जाएगा क्योंकि व्यापार घाटे का मूल कारण समष्टि आर्थिक असंतुलन है।

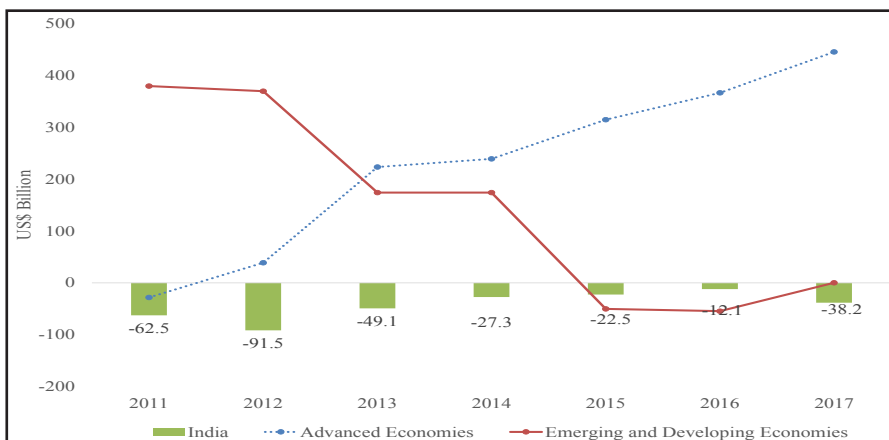
6.3 डब्ल्यू ई ओ तदनुसार सलाह देता है कि, बहुपक्षीय स्तर पर, विरूपणयोग्य बाधाएँ जो कि मंद हो रही वैश्विक अर्थव्यवस्था को और अधिक अस्थिर करेंगी को उठाये बिना, मुख्य प्राथमिकता देशों के लिए सहयोगपूर्वक व्यापार असहमति का समाधान करना, इससे प्रतीत होता है 2019 की शुरुआत से देशों को ऐसा करने की सलाह दी गई है, तेल उत्पादक देशों के द्वारा उत्पादन में कटौती करने के साथ अमरीका भी ईरान से तेल आपूर्ति की कटौती करने के बाद कच्चे तेल के मूल्य बढ़ना शुरू हो गए हैं जबकि आपूर्ति विकार के कारण अन्य वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ने लगे हैं। इन घटनाओं ने भारत जैसे उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के वैदेशिक क्षेत्र की कमजोरी को बढ़ाया है जोकि इनकी आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए कच्चे तेल पर निर्भर है।

6.4 डब्ल्यूटीओ ने अपनी अप्रैल 2019 की प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कहा है कि वृहत्त-व्यापार होने वाली

वस्तुओं ने कमजोर वैश्विक आर्थिक वृद्धि एवं वित्तीय बाजार में अस्थिरता प्रभावित करने के द्वारा विश्व भर में नये एवं प्रतिक्रियात्मक उपायों की शुरुआत के पश्चात् विश्व व्यापार वृद्धि 2017 में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि दर से बहुत अधिक कम 2018 में 3 प्रतिशत की दर पर रही है। इस विज्ञप्ति आगे और यह बताती है कि व्यापार तनाव के अलावा संयुक्त राज्य में फेडरल सरकार शटडाउन तथा वर्ष के अंत की ओर जर्मनी में आटोमेटिव क्षेत्र में उत्पादन समस्याओं सहित व्यापार और उत्पादन अस्थायी झटकों से प्रभावित हुए थे। दूसरी ओर वैश्विक वाणिज्यिक सेवाएं 2018 में 7.7 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई थी परंतु 2017 में 8.4 प्रतिशत से अभी तक कम थी। तथापि, माल संबंधित सेवाएं पिछले वर्ष में 8.3 प्रतिशत से बढ़कर 2018 में 10.6 प्रतिशत बढ़ी थी।

6.5 2018 में देखी गई विश्व व्यापार की मंदी के साथ पिछले वर्ष में भी बीओपी संतुलन की प्रकृति में स्थानित खिसकाव रहा है। चित्र 1 यह दर्शाता है कि 2011 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 28.1 बिलियन अमरीकी डालर का चालू खाता था जो कि उसके बाद से निरंतर कम होता रहा तथा 2017 में 444.7 बिलियन अमरीकी डालर के चालू खाता अधिशेष में तब्दील हो गया। दूसरी ओर उभरते और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं उनके 2011 में 379.0 बिलियन अमरीकी डालर से 2017 में 0.1 बिलियन अमरीकी डालर की चालू खाता अधिशेष स्थिति से फिसल गई। यह उन्नत से कम उन्नत देशों तक विश्व के उपभोक्ता केन्द्र का

चित्र 1: चालू खाता शेष की अंतराष्ट्रीय तुलना



स्रोत: आई एम एफ केवल 2017 तक की सूचना उपलब्ध है।

खिसकाव प्रदर्शित करता है।

6.6 यह उत्पादन एवं व्यापार की वैश्विक मंदी, विश्वभर में व्यापार संरक्षणवाद में बढ़ोतरी तथा उभरते एवं विकासशील देशों में उपभोग केन्द्र के खिसकने के संदर्भ में भारत के व्यापार पर घटनाओं एवं भुगतान शेष मोर्चे पर किए गए विचार के संदर्भ में है।

### भारत के भुगतानशेष संतुलन संबंधी प्रगति

#### भुगतान संतुलन का सिंहावलोकन

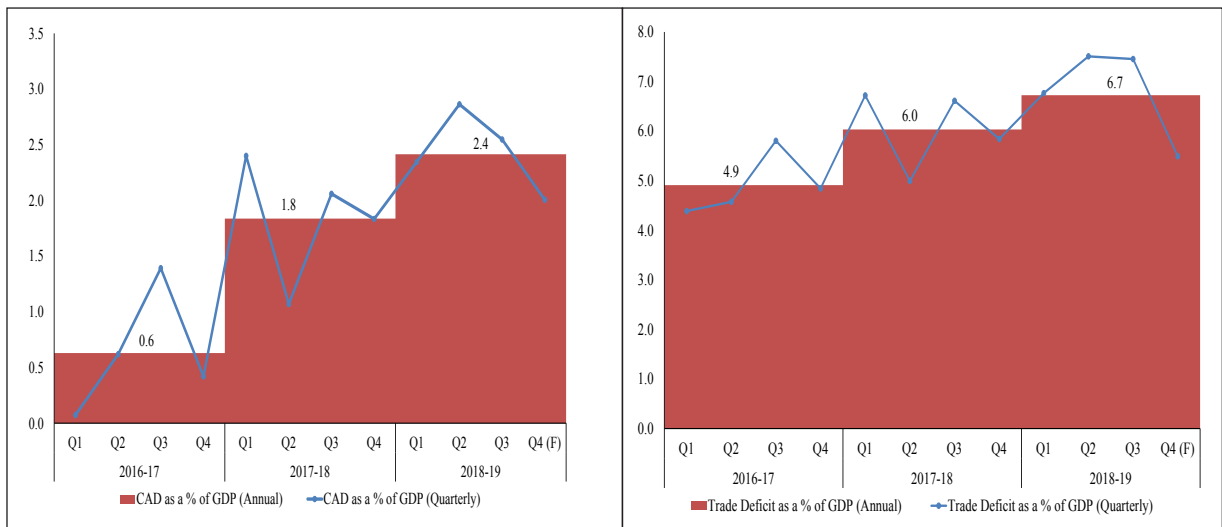
##### चालू खाता विकास

6.7 2018-19 की पहली छमाही के दौरान भारत के भुगतान शेष की स्थिति ने कुछ मंदी के लक्षण दिखाये हैं क्योंकि कच्चे तेल के मूल्य में तेज वृद्धि के कारण चालू खाता घाटा बिगड़ गया है। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल मूल्य में कमी के कारण 2018-19 की तीसरी तिमाही में चालू खाता घाटा कुछ हद तक कम हुआ है। तीसरी तिमाही के अंत तक जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं (अप्रैल-दिसम्बर 2018-19) भारत का चालू खाता घाटा इसी अवधि के लिए एक वर्ष

पूर्व 35.7 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 1.8 प्रतिशत) की तुलना में 51.9 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 2.6 प्रतिशत) रहा था। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों (भारतीय टोकरी) में वृद्धि के कारण चालू खाता घाटा बढ़ता गया जिसका मुख्य कारण उच्चतर व्यापार घाटा है, जिसने आयात की अपेक्षा वस्तु निर्यात वृद्धि को अधिक तेजी से बढ़ाया है। व्यापार घाटा इसी अवधि के दौरान पिछले वर्ष की संगत अवधि में 118.4 बिलियन अमरीकी डालर से 145.3 बिलियन अमरीकी डालर बढ़ गया था।

6.8 भारत का चालू खाता घाटा 2016-17 में जीडीपी के 0.6 प्रतिशत के उच्च स्तर को प्राप्त करने के पश्चात अब कुछ वर्षों से बढ़ रहा है। यह 2017-18 में जीडीपी के 1.8 प्रतिशत बढ़ गया तथा 2018-19 के पूर्ण वर्ष के लिए 2.9 प्रतिशत अनुमानित किया गया है। चालू खाता घाटे में प्रत्याशित वृद्धि वस्तु व्यापार घाटे में वृद्धि से प्रेरित है जोकि जीडीपी के अनुपातिक रूप में 2016-17 में 4.9 प्रतिशत से 2017-18 में 6.0 प्रतिशत तक बढ़ गई तथा इसके अतिरिक्त 2018-19 में 6.7 प्रतिशत तक नीचे गिर गई (चित्र-2)

चित्र 2: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में चालू खाता घाटा एवं व्यापार घाटा



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों पर आधारित

टिप्पणी: एफ: 2018-19 की चौथी तिमाई के लिए पूर्वानुमानित आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

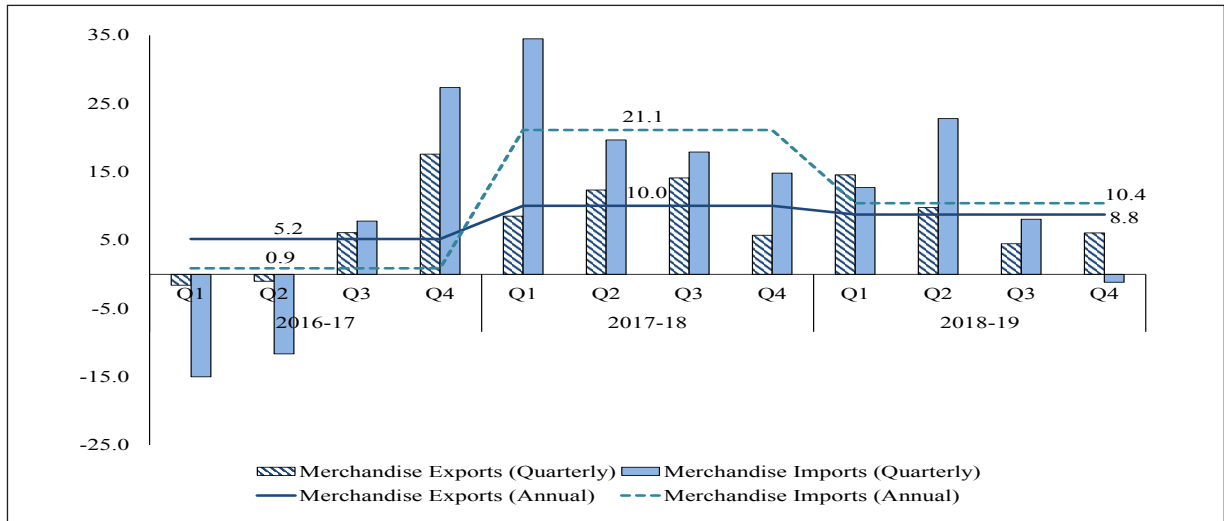
6.9 वस्तु व्यापार घाटे में प्रवृत्ति वस्तु आयात के निवल वस्तु निर्यात की गति को प्रदर्शित करता है। विगत दस वर्षों में वस्तु निर्यात, वस्तु आयात तथा व्यापार शेष में वृहत्त प्रवृत्ति अनुबंध-I में इंगित की गई है। हाल की

अवधि के लिए जैसा चित्र-3 में दर्शाया गया है वस्तु निर्यात एवं वस्तु आयात दोनों की वृद्धि 2016-17 से 2017-18 तक तेजी से बढ़ी थी। तथापि, इसके बाद वस्तु निर्यात की वस्तु निर्यात की वार्षिक वृद्धि

2017-18 में 10 प्रतिशत से 2018-19 में 8.8 प्रतिशत तक गिर गई थी। वस्तु आयात की वार्षिक दर भी 2017-18 में 21.0% से 2018-19 में 10.4 प्रतिशत

तक गिर गई थी। 2018-19 की चौथी तिमाही में वस्तु आयात ने ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की थी जिसने व्यापार और चालू खाता घाटा में थोड़ा सुधार किया।

चित्र 3 वस्तु आयात एवं वस्तु निर्यात की वृद्धि (प्रतिशत)



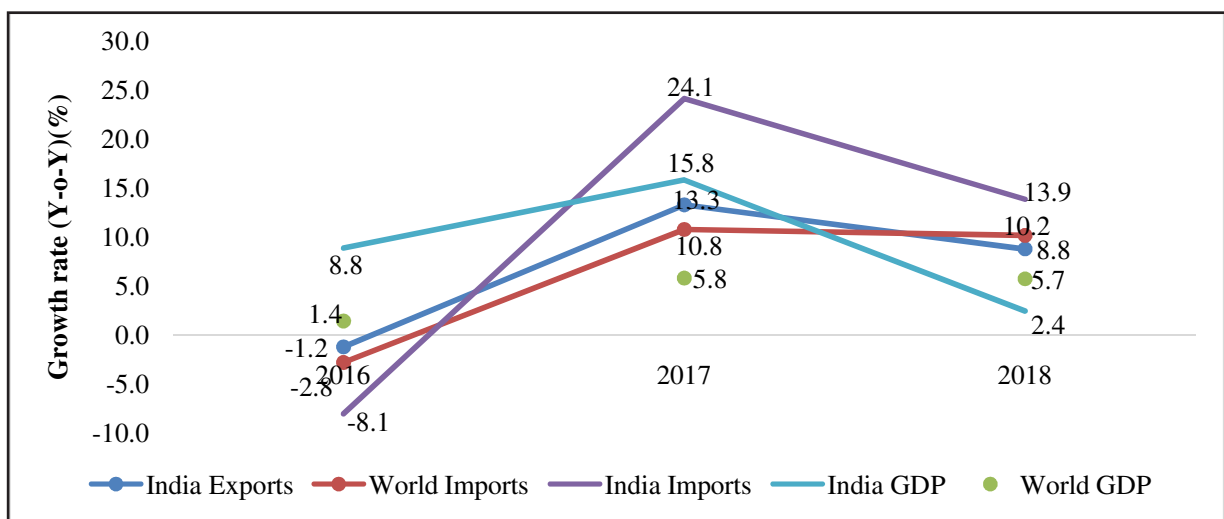
स्रोत-वाणिज्य विभाग के आंकड़े पर आधारित

6.10 वैश्विक संदर्भ में वस्तु निर्यात एवं आयात की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए (चित्र 4) यह प्रतीत होता है कि अन्य घटकों के साथ-साथ 2018-19 में कम जीडीपी वृद्धि के कारण भारत का वस्तु आयात गिर गया जबकि विश्व उत्पादन एवं व्यापार की धीमी

वृद्धि के परिणामस्वरूप वस्तु निर्यात की वृद्धि धीमी रही हो सकती है।

6.11 वस्तु निर्यात में वृद्धि 2016-17 में 5.2% से 2018-19 में 8.8% तक मुख्य रूप से पेट्रोलियम, तेल

चित्र 4: भारत के निर्यात एवं आयात पर वैश्विक एवं घरेलू अर्थव्यवस्था का प्रभाव



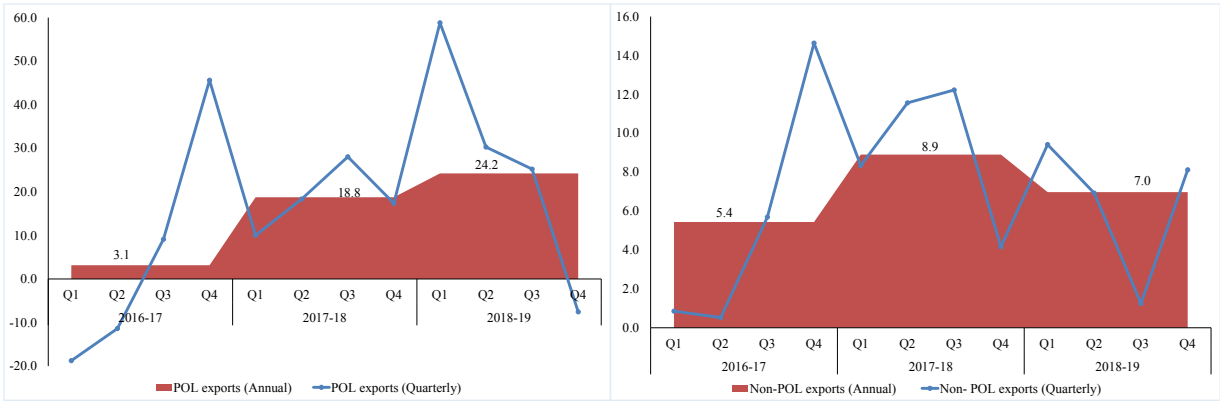
स्रोत: विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) से भारत का आयात/निर्यात एवं विश्व आयात हेतु नवीनतम सुमेलित आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) 2019 से भारत एवं विश्व जीडीपी।

और स्नेहक (पीओएल) निर्यात में उच्च वृद्धि के परिणामस्वरूप हुई जोकि 2016-17 में 3.1 प्रतिशत से 2018-19 में 24.2% तक बढ़ी थी जबकि इसी अवधि के दौरान गैर पीओएल निर्यात 5.4% से 7.0 प्रतिशत तक संतुलित रूप से बढ़े थे (चित्र 5)। तथापि, 2018-19 की पहली तिमाही से पीओएल निर्यात की वृद्धि दर निरंतर गिर रही है तथा चौथी तिमाही में

ऋणात्मक हो गई। अगर ऐसा ही हो तो, पेट्रोलियम पदार्थ 2018-19 में 11.4 पर भारत के निर्यात टोकरी में बड़ा हिस्सा बना रहेगा।

6.12 2016-17 में 0.9% से 2018-19 में 10.4% तक वस्तु आयात में वृद्धि को 2016-17 में 4.8% से 2018-19 में 29.7% तक पीओएल आयात की

**चित्र 5: पीओएल तथा गैर पीओएल निर्यातों में वृद्धि ( प्रतिशत )**

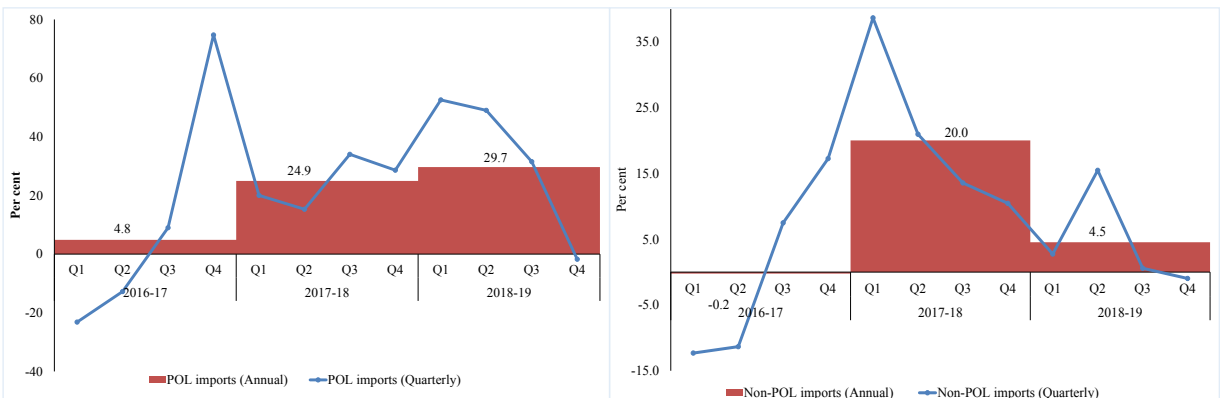


स्रोत: वाणिज्य विभाग के आंकड़ों पर आधारित।

वृद्धि दर में तीव्र बढ़ोतरी को माना जा सकता है। गैर पीओएल आयात भी 2016-17 में 0.2% से 2018-19 में 4.5% तक सामान्य रूप से बढ़ा है (चित्र 6), संभवतः अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्शा रहा है। यह और भी अधिक प्रतीत होता है जैसाकि 2018-19 की चौथी तिमाही में पीओएल और गैर पीओएल आयात दोनों में

ऋणात्मक वृद्धिदर दर्ज हुई है। फिर भी, आयाम टोकरी में कच्चा पेट्रोलियम: कच्चा तेल 22.2% के हिस्से के साथ 2018-19 में सबसे बड़ी आयातित वस्तु बनी हुई है। जिसके बाद 6.4%, 5.3% तथा 5.2% के हिस्से के साथ क्रमशः स्वर्ण/चांदी, मोती, बहुमूल्य, अर्धबहुमूल्य पत्थर तथा पेट्रोलियम पदार्थ आते हैं।

**चित्र 6: पीओएल एवं गैर पीओएल आयातों में वृद्धि ( प्रतिशत )**

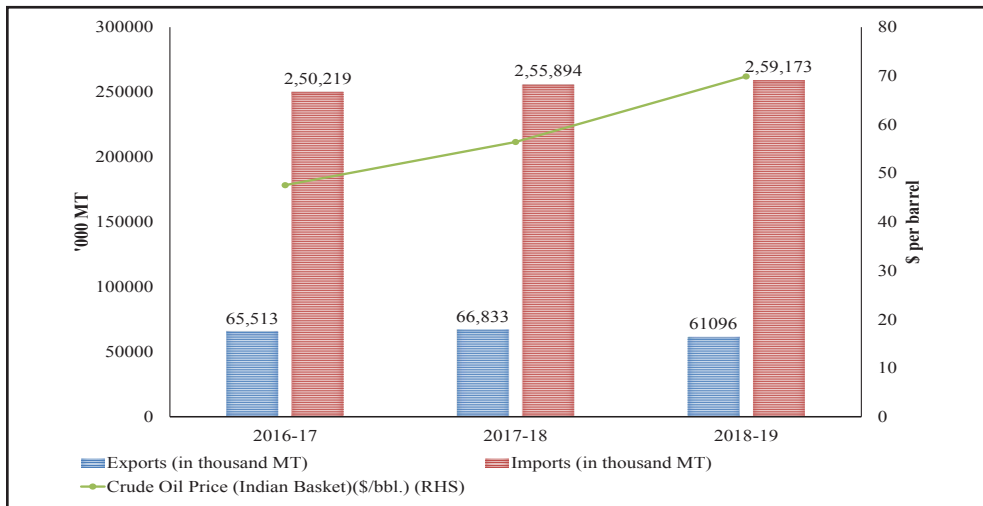


स्रोत: वाणिज्य विभाग के आंकड़ों पर आधारित।

6.13 चित्र 7 में 2016-17 से 2018-19 के दौरान भारत के पीओएल व्यापार का एक रुचिकर विवेचना बताता है। 2016-17 से 2018-19 तक पीओएल आयातों की वृद्धि में बढ़ोत्तरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य वृद्धि तथा भारत द्वारा उपभोग मात्रा दोनों के कारण थी। तथापि, पीओएल निर्यात की वृद्धि केवल भारत

द्वारा निर्यात की गई मात्रा के रूप में मूल्य वृद्धि से प्रेरित थी जो कि वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक की गई वास्तविक संविदा थी। यह प्रकट करता है कि भारत के पीओएल निर्यात पर विश्व की निर्भरता की अपेक्षा भारत पीओएल आयात पर अधिक निर्भर है।

चित्र 7: पीओएल निर्यात तथा आयात तथा कच्चा तेल मूल्य ( भारतीय टोकरी ) की मात्रा।

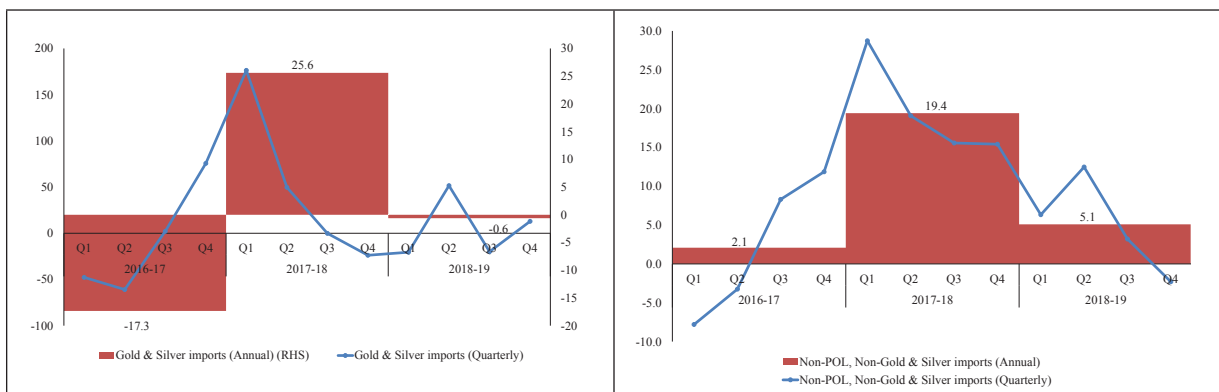


स्रोत: वाणिज्य विभाग के आंकड़ों पर आधारित।

6.14 गैर पीओएल आयातों के भीतर स्वर्ण एवं चांदी आयात की वार्षिक वृद्धि के संबंध में स्पष्ट गति देखी जा सकती है, जो कि 2016-17 में -17.3% से 2017-18 में 25.6% तक बढ़ गई थी, तथा 2018-19 में -0.6% तक कम हो गई थी। गैर पीओएल, गैर स्वर्ण तथा चांदी आयात में 2016-17 में 2.1% से 2017-18 में 19.4% तक वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी के

साथ यही प्रवृत्ति देखी गई थी तथा 2018-19 में 5.1 प्रतिशत तक की गति में कमी स्वर्ण एवं चांदी आयात से भिन्न (चित्र 8) जिसकी वृद्धि 2018-19 में फिर से ऋणात्मक हो गई यद्यपि उस हद तक नहीं जितनी की 2016-17 में थी। स्वर्ण एवं चांदी आयात की सकारात्मक चौथी तिमाही वृद्धि ने इसकी वृद्धि को पूरे वर्ष के लिए ऐसे ही गिरावट हेतु स्वीकार नहीं किया

चित्र 8: स्वर्ण एवं चांदी आयातों एवं गैर पीओएल, गैर-स्वर्ण एवं चांदी आयातों में वृद्धि दर



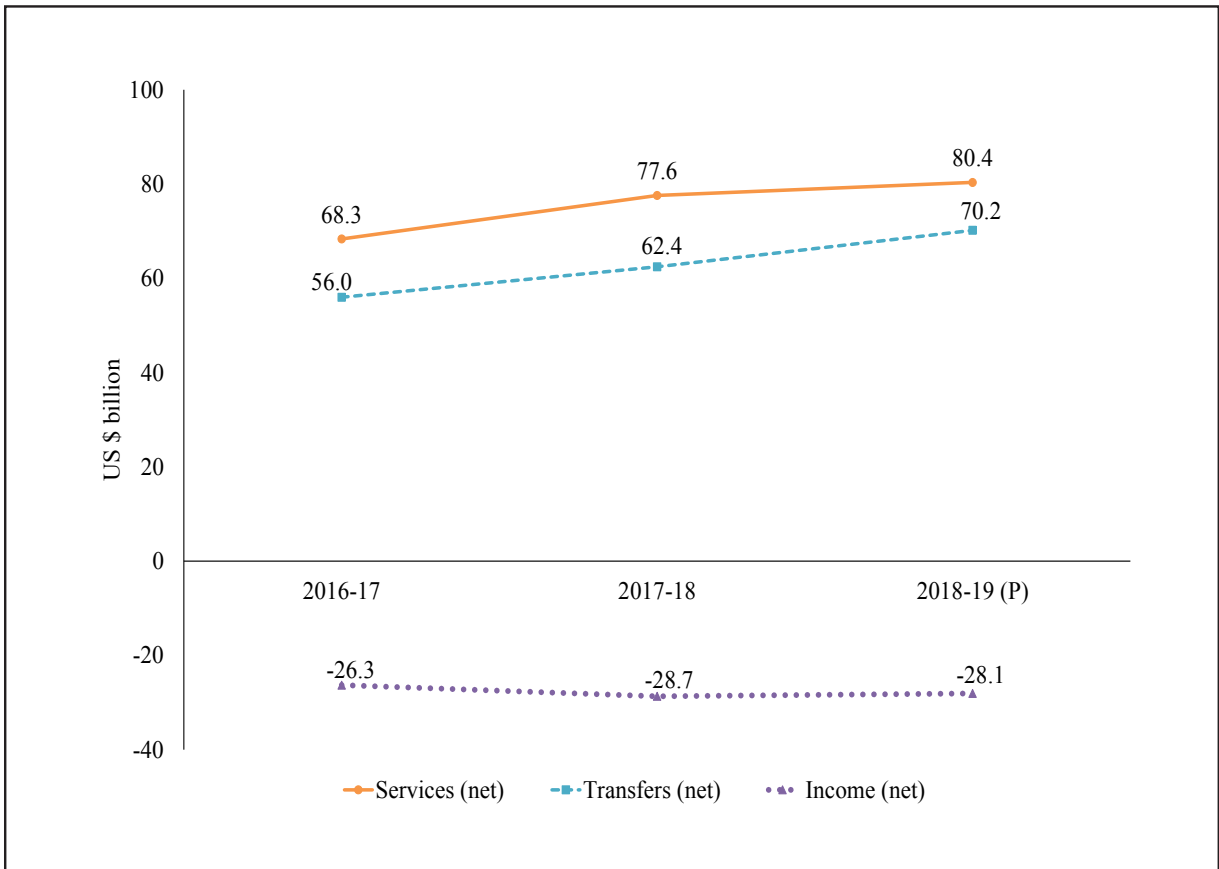
स्रोत: वाणिज्य विभाग के आंकड़ों पर आधारित।

था जबकि चौथी तिमाही में गैर पीओएल, गैर स्वर्ण एवं चांदी आयात की नकारात्मक वृद्धि दर ने उल्लेखनीय रूप से इसकी वृद्धि दर को घटा दिया था।

6.15 निवल अदृश्य के तीन प्रमुख घटकों को निवल सेवाओं ने वही प्रवृत्ति का अनुसरण किया है जैसी व्यापारिक प्राप्तियों ने 2016-17 से 2018-19 तक की थी जो कि 2018-19 में धीमी होने से पहले

2017-18 में प्रारंभिक रूप से तेजी से बढ़ी थी (चित्र 9)। निवल अंतरण की वृद्धि तथा तीव्र गति से बढ़ती रही जबकि इसी अवधि के दौरान निवल घटक आय में वृद्धि नहीं थी। वस्तु व्यापार घाटे को वित्त व्यापार घाटे को वित्त पोषित करने के लिए निवल सेवाओं का योगदान 2016-17 में 62.2% से 2018-19 में 43.7% तक गिर गया जो हाल ही में सेवा निर्यात के

चित्र 9: निवल सेवाएं, निवल अंतरण एवं निवल आय ( बिलियन US\$ में )

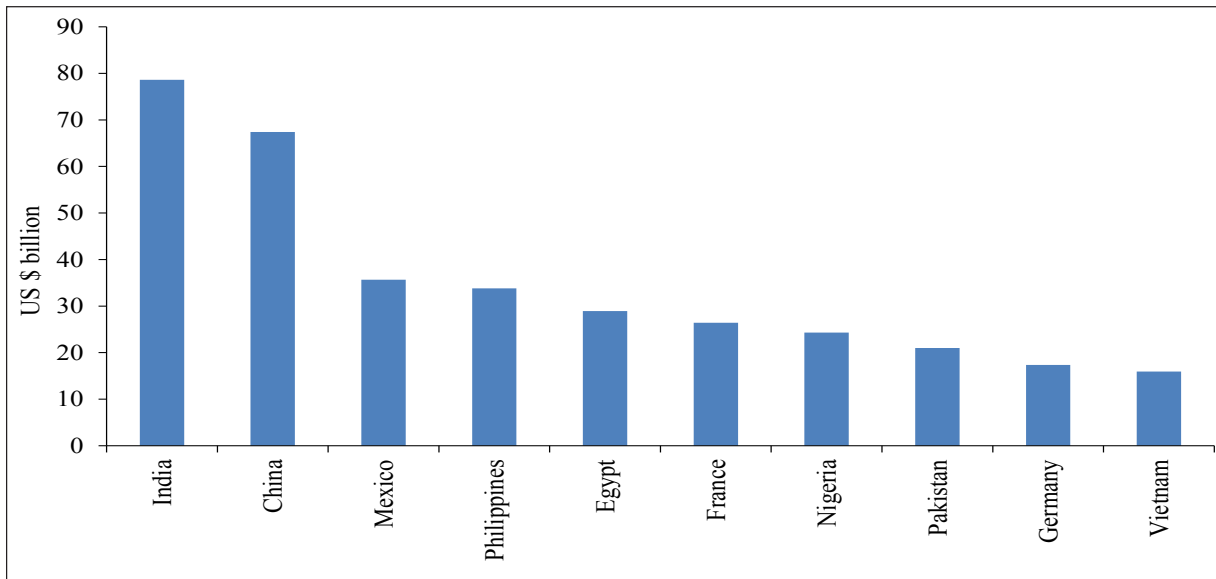


स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों एवं मंत्रालय के अनुमानों पर आधारित।  
टिप्पणी: पी: अंतिम

मौन प्रदर्शन को प्रदर्शित कर रहा है। वित्तीय सेवाओं के साथ, कुल सेवा प्राप्तियों के लगभग 40 प्रतिशत के लिए साफ्टवेयर सेवाएं, लेखांकन सेवाएं, सेवा निर्यात में प्रमुख चालक रही है। विगत दस वर्षों में भारत के सेवा व्यापार में व्यापक प्रवृत्ति अनुबंध-I में दर्शाया गया है।

6.16 विदेश में कार्यरत भारतीयों द्वारा मुख्य रूप से प्रतिनिधित्वकारी विप्रेषण, निवल निजी अंतरण प्राप्तियां 2017-18 में 11.5% तथा 2016-17 में 10.6% की तुलना में 2018-19 (अ) में 12.4% बढ़ गई थी (चित्र-9)। तेल मूल्य बढ़ने से खाड़ी देशों में बेहतर आय स्थिति ने विप्रेषण में इस वृद्धि को प्रभावित किया

चित्र 10: 2018 में प्रेषित शीर्ष धन प्राप्तकर्ता



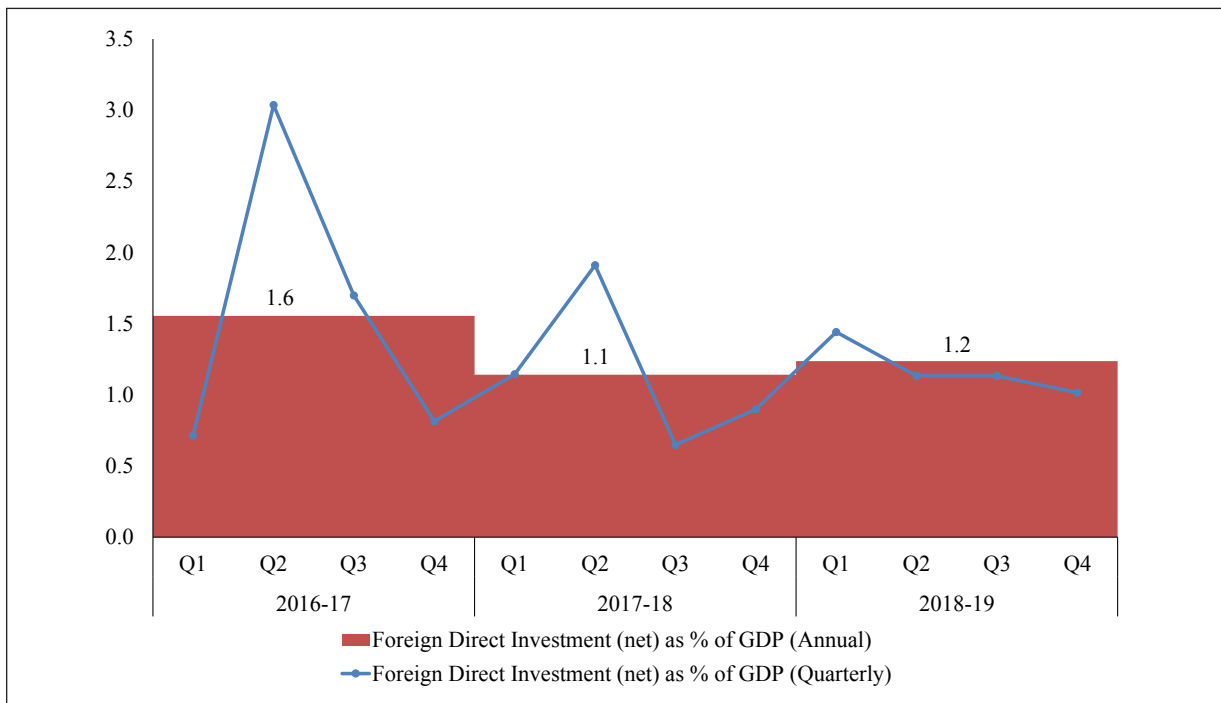
स्रोत: विश्व बैंक के नवीनतम उपलब्ध आंकड़े

हो क्योंकि विप्रेषण का उल्लेखनीय हिस्सा इन देशों से आता है। विश्व बैंक (अप्रैल 2019) के अनुसार भारत 2018 में चीन, मैक्सिको, फिलीपींस एवं मिस्र के बाद 78.6 बिलियन अमरीकी डालर (चित्र 10) पर सबसे

उच्च स्तर पर शीर्षस्थ धनप्रेषण प्रवाह के साथ शीर्ष प्रेषित धन प्राप्तकर्ता देशों में रहा था।

6.17 2018-19 के दौरान, निवल विदेशी निवेश

चित्र 11: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों पर आधारित।



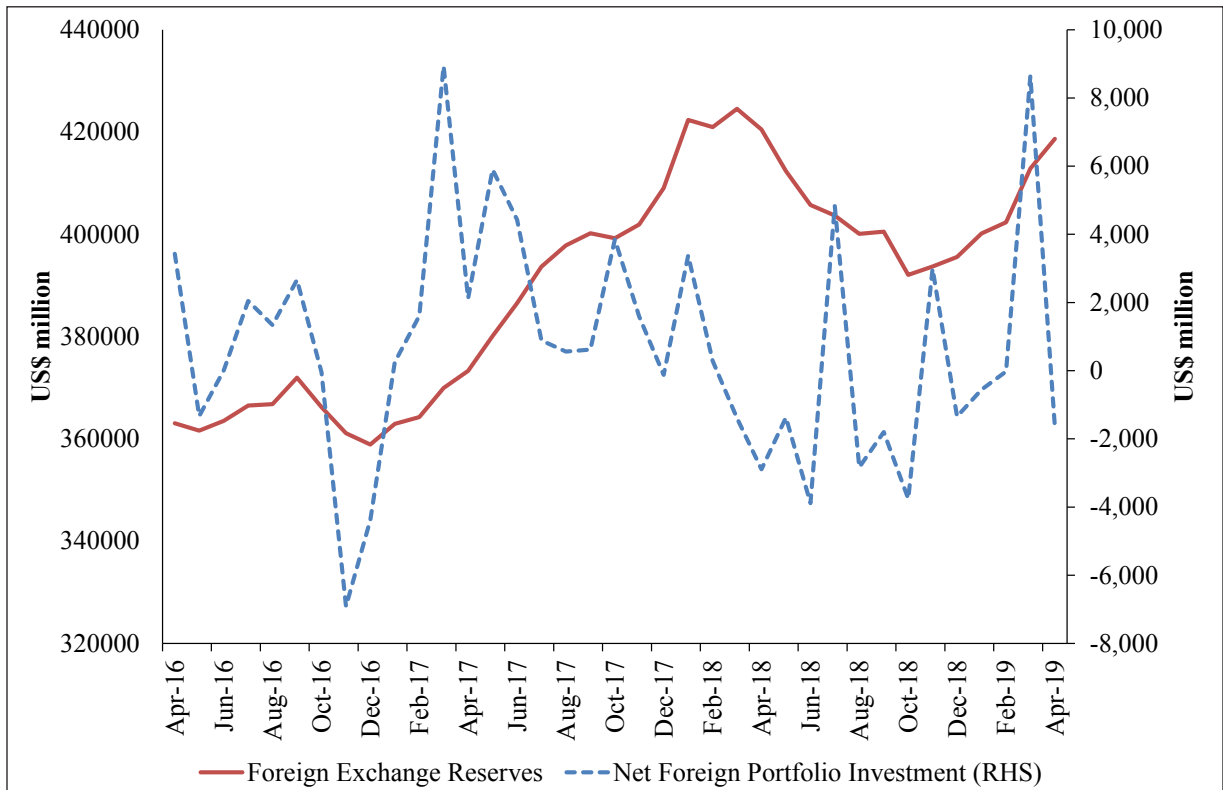
2017-18 की संगत अवधि में 52.4 बिलियन अमरीकी डालर की अपेक्षा 31.3 बिलियन अमरीकी डालर गिर गया था। जबर्दस्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) प्रवाह वैश्विक जोखिम निवारण की वृद्धि को विचार करते हुए पोर्टफोलियो निवेश के अंतर्गत आहरणों और अधिक महत्वपूर्ण साबित हुए थे। जीडीपी के अनुपात के रूप में निवल एफडीआई 2018-19 में 1.2% तक बढ़ने से पहले 2016-17 में 1.6% से 1.1% तक गिर गया था (चित्र 11)।

6.18 पूंजी प्रवाह के अन्य रूपों के बीच, बैंकिंग पूंजी ने 2018-19 (अप्रैल-दिसंबर) में 15.5 बिलियन अमरीकी डालर के निवल प्रवाह दर्ज किया था जो कि पिछले वर्ष की संगत अवधि में 11.6 बिलियन अमरीकी डालर से 34% अधिक था। पूंजी प्रवाह निर्माणकारी ऋण के बीच निवल विदेशी सहायता पिछले वर्ष की संगत अवधि में 1.5 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2018-19 (अप्रैल-दिसंबर) में 42.7% बढ़कर 2.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गयी थी। निवल विदेशी वाणिज्यिक

उधार (ईसीबी) ने भी पिछले वर्ष की संगत अवधि में 1.2 बिलियन अमरीकी डालर के निवल बर्हिप्रवाह के अपेक्षा 2018-19 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान 2.8 बिलियन अमरीकी डालर का निवल बर्हिप्रवाह महसूस किया गया था जोकि देश में संभवतः ऋण मुश्किल को प्रदर्शित करता है। निवल एनआरआई जमा 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में 5.0 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2018-19 (अप्रैल-दिसंबर) में 7.0 बिलियन अमरीकी डालर बढ़ा था, जबकि निवल लघु-अवधि ट्रेड क्रेडिट ने अप्रैल-दिसंबर 2018 के दौरान तीव्र गिरावट दर्ज की थी क्योंकि आयात संकुचन आरंभ होना शुरू हो गया था। कुल मिलाकर, चालू खाता घाटे में वित्त पोषण की कमी के कारण पूंजी प्रवाह कम हो गया था। जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल-दिसंबर 2018 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में 17.5 बिलियन अमरीकी डालर का हास हुआ था। 2013-14 से 2018-19 (अप्रैल-दिसंबर) तक भुगतान शेष तालिका अनुबंध-II (तालिका 3) पर दिया गया है।

6.19 लंबी अवधि तक चालू खाता घाटे के वित्त पोषण

चित्र-12 निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एवं विदेशी मुद्रा भंडार में मासिक परिवर्तन



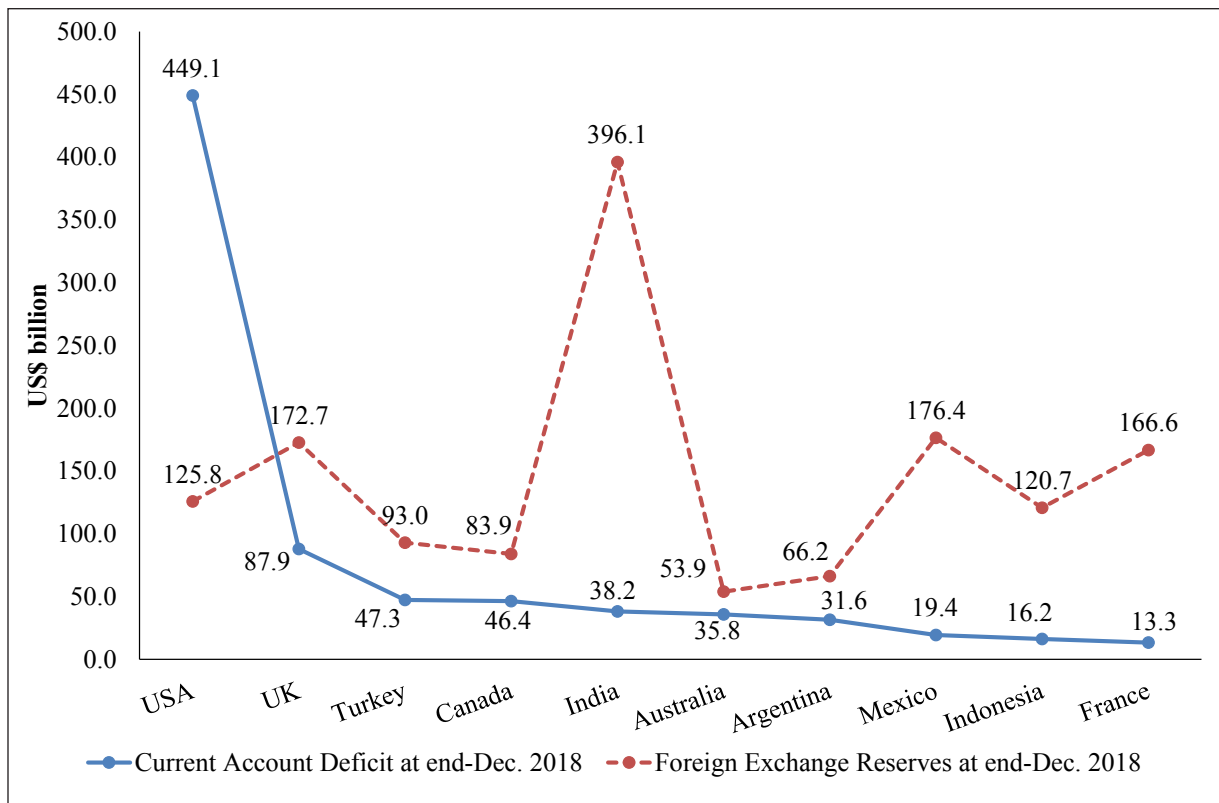
स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े पर आधारित

के साधनों में बदलाव समझने योग्य है। 2009-14 में निवल पोर्टफोलियो निवेश ने चालू खाता घाटे को 45.6 प्रतिशत वित्त पोषित किया था लेकिन 2014-19 में यह 17.1 प्रतिशत तक गिर गया था। इस तरह पिछली अवधि की तुलना में 2014-19 में चालू खाता घाटे के वित्त पोषण में पूंजी पलायन के प्रति कम नाजुक हो गया था। हालही के समय में चालू खाता घाटे को वित्तपोषित करने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशों पर कम हुई निर्भरता इस तथ्य में भी दर्शायी जाती है कि देश में विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (चित्र 12) में परिवर्तन के साथ कोई सह संबंध स्थापित नहीं करता है।

6.20 14 जून 2019 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार 422.2 बिलियन अमेरिकी डालर पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित परिसंपत्तियों में मूल्य परिवर्तन के साथ-साथ भुगतान शेष आधार पर भंडार में परिवर्तन के कारण विदेशी मुद्रा भंडार के स्तर में परिवर्तन हो सकता है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के

दौरान 39.1 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2018 के दौरान संज्ञात्मक शर्तों (मूल्यांकन प्रभाव सहित) में विदेशी मुद्रा भंडार 29.0 बिलियन अमरीकी डालर कम हो गया था। तथापि, भुगतान शेष आधार (अर्थात मूल्यांकन प्रभावों को छोड़कर) पर विदेशी मुद्रा भंडार इसी वर्ष की संगत अवधि के दौरान 30.3 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2018 के दौरान 17.5 बिलियन अमरीकी डालर घट गया था। मुख्य रूप से प्रमुख मुद्राओं के विरुद्ध अमरीकी डालर की वृद्धि विचार करते हुए हानि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 8.8 बिलियन अमरीकी डालर के मूल्यांकन लाभ के बाद अप्रैल-दिसंबर 2018 के दौरान 11.5 बिलियन अमरीकी डालर की मूल्यांकन हानि थी। विदेशी मुद्रा भंडार (अमरीकी बिलियन डालर) में परिवर्तन का सार दर्शाता हुई सारणी अनुबंध प्प (सारणी 4) में दिया गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का आयात कवर मार्च 2018 के

चित्र: 13 उच्चतम चालू खाता घाटे तथा उनके विदेशी मुद्रा भंडार, 2018 के साथ देश

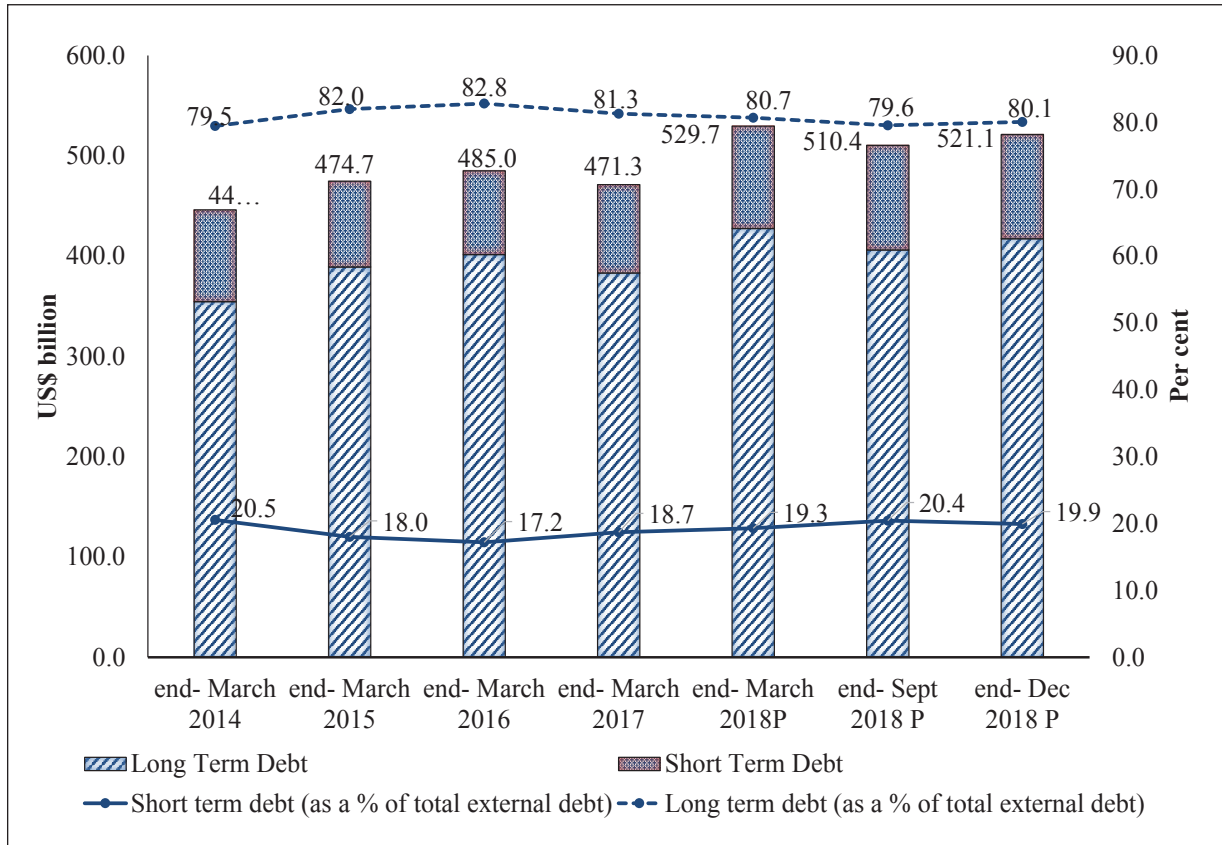


स्रोत: आईएफएस, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के आधार पर

अंत तक 10.9 माह से दिसंबर 2018 के अंत तक 9.1 माह तक कम हो गया। तदुपरांत तथापि 2018-19 की चौथी तिमाही में सांक्रतिक शर्तो में विदेशी मुद्रा की निवल अभिवृद्धि 17.3 बिलियन अमरीकी डालर रही थी जो आंशिक रूप से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की मजबूती प्रदर्शित कर रही है।

6.21 चालू खाता घाटे पर चलने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक तथा विश्व के सभी देशों के बीच आठवां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है। (चित्र 13)।

चित्र: 14 भारत का बकाया विदेशी ऋण



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक तथा दिसंबर 2018 (नवीनतम उपलब्ध) के अंत में भारत के विदेशी ऋण की तिमाही रिपोर्ट, आर्थिक कार्य विभाग टिप्पणी: पी. अनंतिम

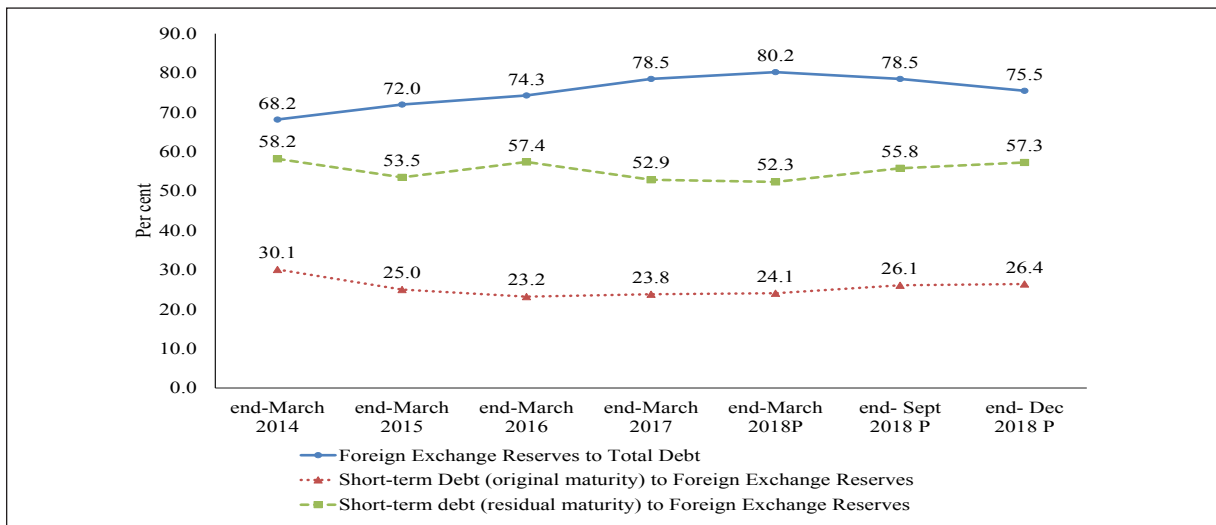
### विदेशी ऋण

6.22 भारत का विदेशी ऋण मार्च, 2018 के अंत पर इसके स्तर से 1.6 प्रतिशत की कमी के साथ दिसंबर, 2018 के अंत तक 521.2 बिलियन अमरीकी डालर था (चित्र 14)। मार्च अंत 2018 की तुलना में दिसंबर 2018 के अंत में दीर्घावधि ऋण 417.3 बिलियन अमरीकी डालर तक 2.4 प्रतिशत गिर गया था यद्यपि इसका हिस्सा इसी अवधि के दौरान 80.7% की तुलना में 80.1 प्रतिशत कमोबेश समान ही था। 2014 से इस हिस्से की स्थिरता सुस्पष्ट रही है। लघु

अवधि ऋण व्यापार संबंधित ऋण में बढ़ोत्तरी के कारण मुख्य रूप से मार्च अंत 2018 की तुलना में दिसंबर के अंत 2018 में 1.7 प्रतिशत बढ़ गए थे।

6.23 मूल परिपक्वता के अल्पकालिक ऋणों का विदेशी मुद्रा भंडार अनुपात मार्च अंत 2018 के 24.1 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर अंत 2018 में 26.4 प्रतिशत के साथ कुल विदेशी ऋण के लिए विदेशी मुद्रा कवर में मार्च 2018 के अंत में 80.2 प्रतिशत से दिसंबर 2018 के अंत में 75.5 प्रतिशत तक कम हो गया था।

चित्र 15: विदेशी मुद्रा भंडार और ऋण

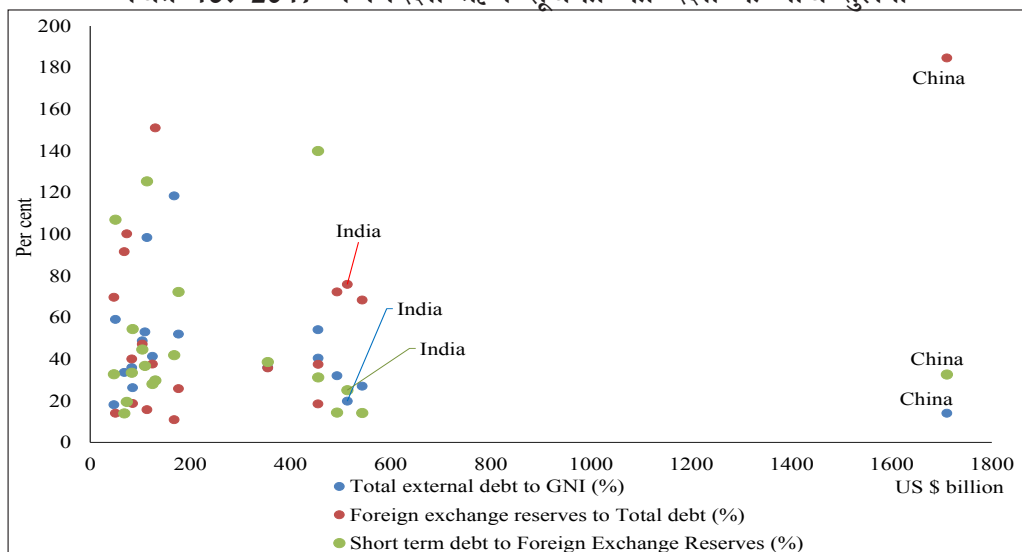


स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक तथा आर्थिक कार्य विभाग की दिसम्बर 2018 (नवीनतम उपलब्ध) के अंत में भारत के विदेशी ऋण की तिमाही रिपोर्ट  
टिप्पणी: पी अनंतिमा 14 जून 2019 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार 422.2 बिलियन अमरीकी डालर

विदेशी मुद्रा भंडार की शेष परिपक्वता अवधि तक अल्प-कालिक ऋण का अनुपात भी इसी अवधि के दौरान 52.3 प्रतिशत से 57.3 तक बढ़ा है (चित्र 15)। कुल विदेशी ऋण में शेष परिपक्वता अवधि द्वारा अल्पकालिक ऋण का भाग, जो कि एक वर्ष में सेवा सविदागत बाध्यता की नकदी की जरूरतों का मूल्यांकन करने में सहायक है, नकदी की स्थिति में वृद्धि को दर्शाते हुए मार्च, 2018 के अंत में 42.0 प्रतिशत की अपेक्षा दिसंबर 2018 के अंत में 43.5 प्रतिशत था।

6.24 विश्व बैंक के आंकड़ों पर आधारित विदेशी ऋण की अंतर्राष्ट्रीय तुलना यह दर्शाती है कि 2017 में शीर्ष 20 विकासशील कर्जदार देशों में सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) अनुपात में भारत का विदेशी ऋण 19.8 प्रतिशत था जो कि नीचे से चौथा स्थान था, जबकि चीन का 14 प्रतिशत (चित्र 16) के साथ न्यूनतम अनुपात में रहना जारी है। विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में विदेशी ऋण का समावेश है, भारत का 75.9% के साथ शीर्ष से पांचवां स्थान है, जबकि शीर्ष 20

चित्र 16: 2017 में विदेशी ऋण सूचकों की देशों के बीच तुलना



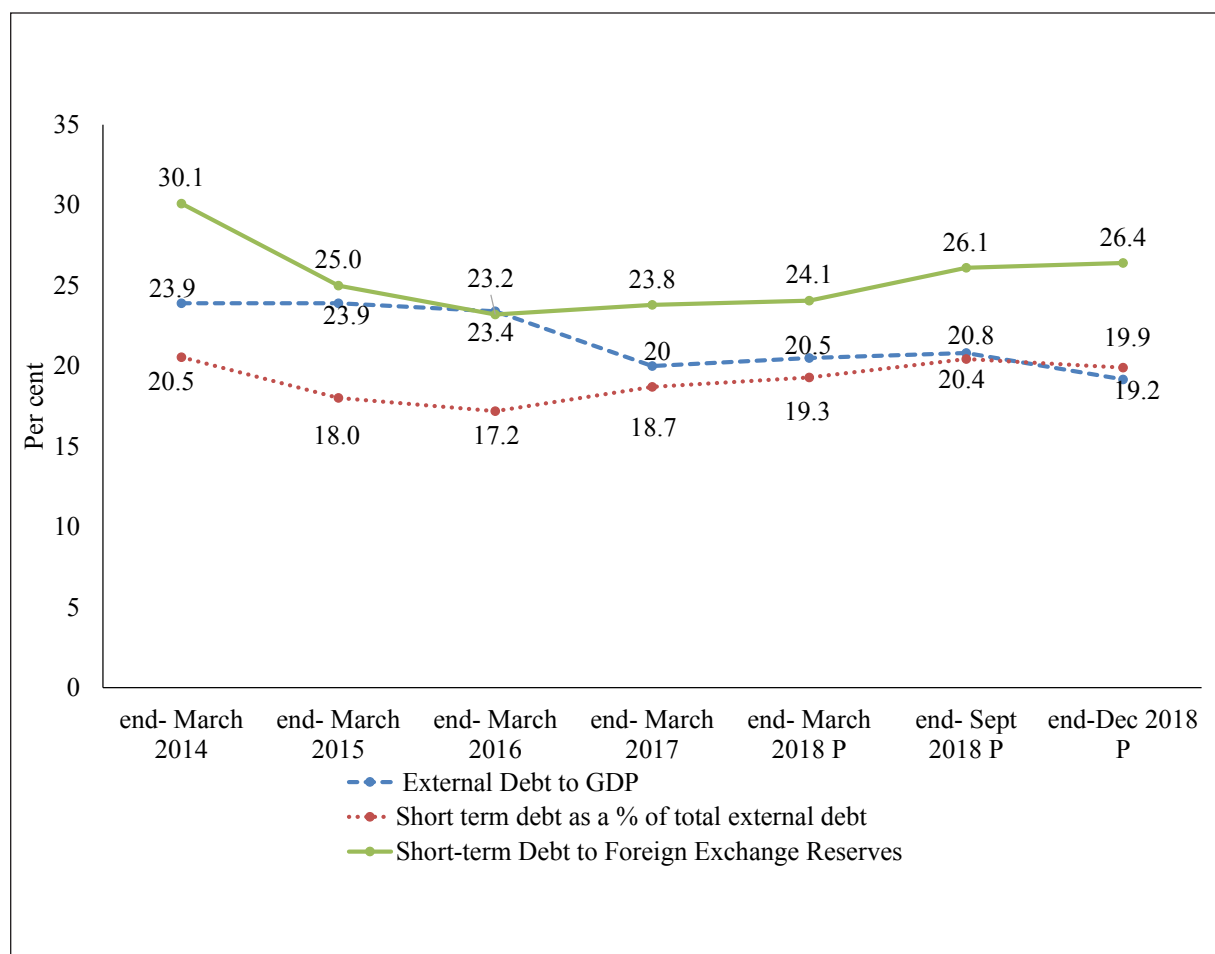
स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी, 2019 विश्व बैंक

विकासशील कर्जदार देशों (चित्र 16) में विदेशी मुद्रा भंडार में 25.1 प्रतिशत अल्पकालिक ऋण के साथ भारत का नीचे से पांचवां स्थान है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार यद्यपि भारत विकासशील देशों (चीन और ब्राजील के पश्चात) में तीसरा बड़ा कर्जदार देश (कुल राशि में) है, इसके ऋण की औसत अवधि बहुत अधिक है, यह देखते हुए कि कुल ऋणों में लघु अवधि ऋण का अनुपात केवल लगभग 19.0 प्रतिशत है जबकि चीन का सही अनुपात 69% है। ऋण की उच्चतर अवधि रोल ओवर रिस्क को कम करती है।

6.25 चित्र 17 भारत के मूल विदेशी ऋण सूचक को संक्षिप्त करते हुए दर्शाता है कि भारत का विदेशी ऋण अस्थिर नहीं है।

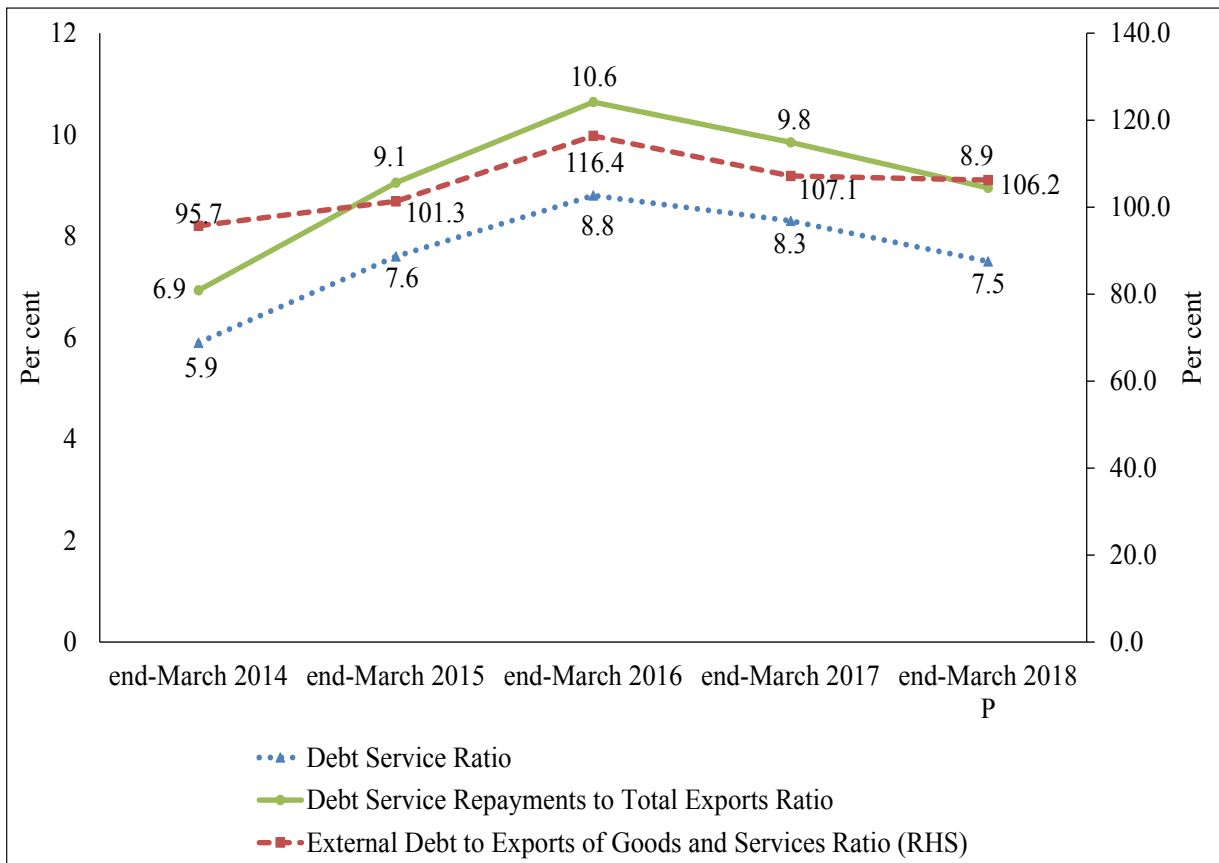
6.26 ऋण सेवा अनुपात इस दावे को दर्शाता है कि फिलहाल की प्राप्तियों पर विदेशी ऋण की अदायगी, ऋण सेवा बाध्यता की अदायगी के कारण बीओपी पर की गई मांग का माप है ऋण सेवा अनुपात 2016 तक बढ़ा है तथा 2016 में 8.8% से 2017 में 8.3% तक 2018 (मार्च अंत) (चित्र 18) में 7.5% तक लगातार कम हुआ है। निर्यात अनुपात में कुल विदेशी ऋण, ऋण स्थिरता का अन्य माप, 2014 से 2016 तक बढ़ा है तथा इसके पश्चात मार्च अंत 2017 में 107.1% तथा मार्च अंत 2018 (चित्र 18) में 106.2% तक कम हुआ है। आगे, वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल निर्यात में ऋण सेवा चुकौती (मूलधन और ब्याज सहित) 2016 तक बढ़ने की तथा इसके पश्चात 2017 (9.8%) और 2018 (8.9%) (चित्र 18) में घटने

चित्र 17 विदेशी ऋण मूल सूचक



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक तथा आर्थिक कार्य विभाग की दिसम्बर 2018 (नवीनतम उपलब्ध) के अंत में भारत के विदेशी ऋण की तिमाही रिपोर्ट।  
टिप्पणी: पी अनंतिम।

चित्र 18: ऋण स्थिरता का सूचक



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों पर आधारित।  
टिप्पणी: पी. अनतिम।

की उसी प्रवृत्ति को दर्शाती है। ऋण सेवा, निर्यात में कुल विदेशी ऋण और निर्यात में ऋण सेवा का घटता अनुपात भारत के लिए हितकारी हो सकता है।

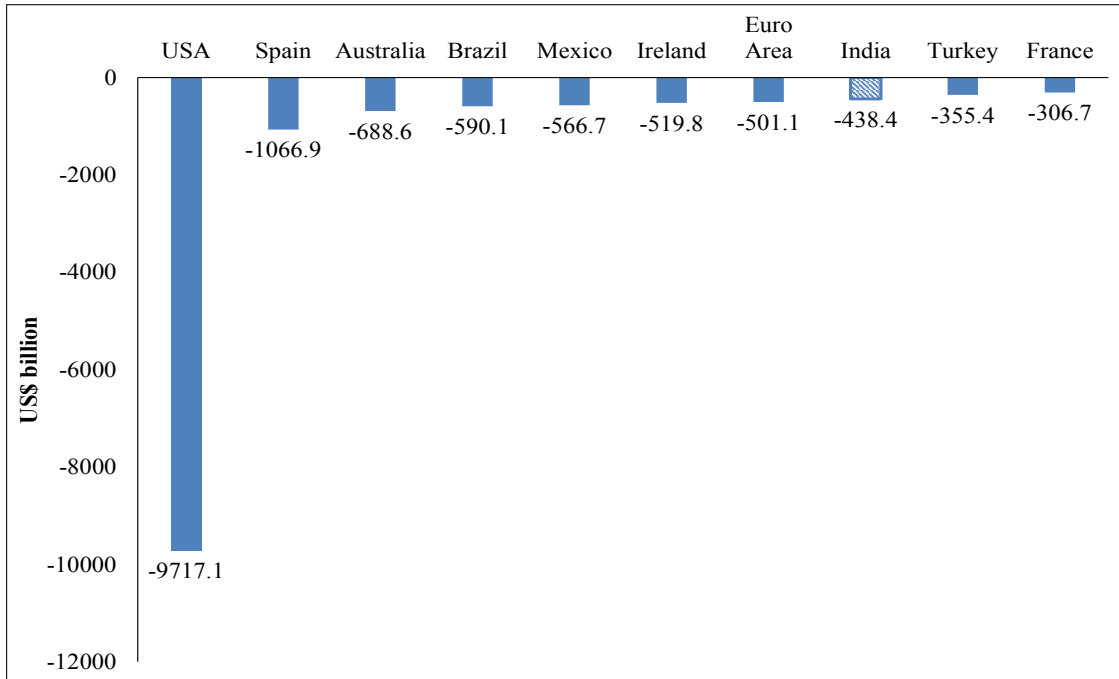
### निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति

6.27 अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति एक सांख्यिकीय विवरण है जो एक समय में अर्थव्यवस्था (आई आई टी) के निवासियों की वित्तीय आस्तियों जो अनिवासियों पर दावे अथवा आरक्षित आस्तियों के रूप में रखे गए स्वर्ण बुलियन हैं; अर्थव्यवस्था के निवासियों तथा गैर निवासियों (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) (आईएमएफ) की देनदारियों के मूल्य को दर्शाता है। आस्तियों और देनदारियों में अंतर आईआईपी में निवल स्थिति का है और यह या तो शेष विश्व के निवल दावे या निवल देनदारियों को प्रस्तुत करता है। धनात्मक एनआईआईपी

मूल्य एक लेनदार देश को दर्शाता है, जबकि ऋणात्मक मूल्य कर्जदार देश को दर्शाता है।

6.28 वर्ष 2018 में निवल आईआईपी घाटे वाली 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में संयुक्त राज्य 9.7 ट्रिलियन अमरीकी डालर के निवल आईआईपी घाटे के साथ पहले स्थान पर है, इसके पश्चात स्पेन (1.1 ट्रिलियन अमरीकी डालर) आस्ट्रेलिया (0.7 ट्रिलियन) हैं (चित्र 19)। वर्ष 2018 में भारत का निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश घाटा अधिकतम से आठवें स्थान पर है, जो कि 2013 में 323.2 बिलियन अमरीकी डालर से 2018 में 438.4 बिलियन अमरीकी डालर तक 35.6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी से निरंतर बढ़ रही है। पिछले वर्ष 2017 की तुलना में भारत में निवल आईआईपी घाटा 2017 में 426.6 बिलियन अमरीकी डालर से 2.8 प्रतिशत बढ़कर 2018 में 438.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है।

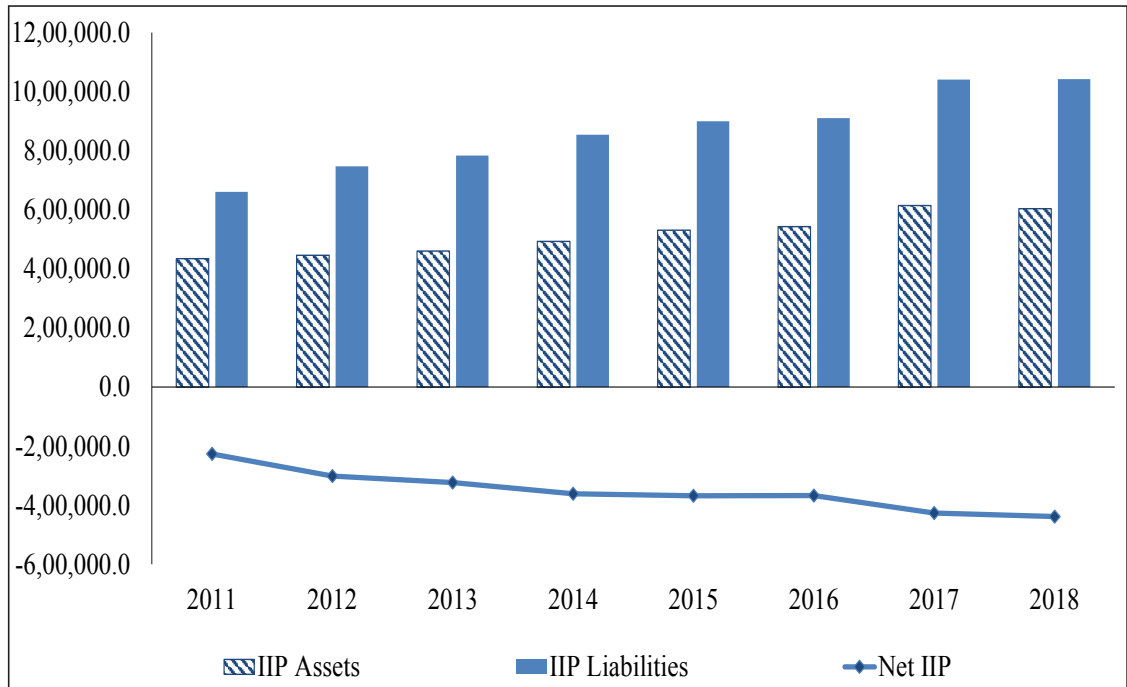
चित्र 19: 2018 में शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में निवल आईआईपी घाटा



स्रोत: आईएमएफ

6.29 चित्र 20 यह दर्शाता है कि 2011 से 2018 तक भारत में तदनु रूप अवधि में आईआईपी देनदारियों में लगातार वृद्धि होने के कारण निवल आईआईपी में लगातार गिरावट हुई है।

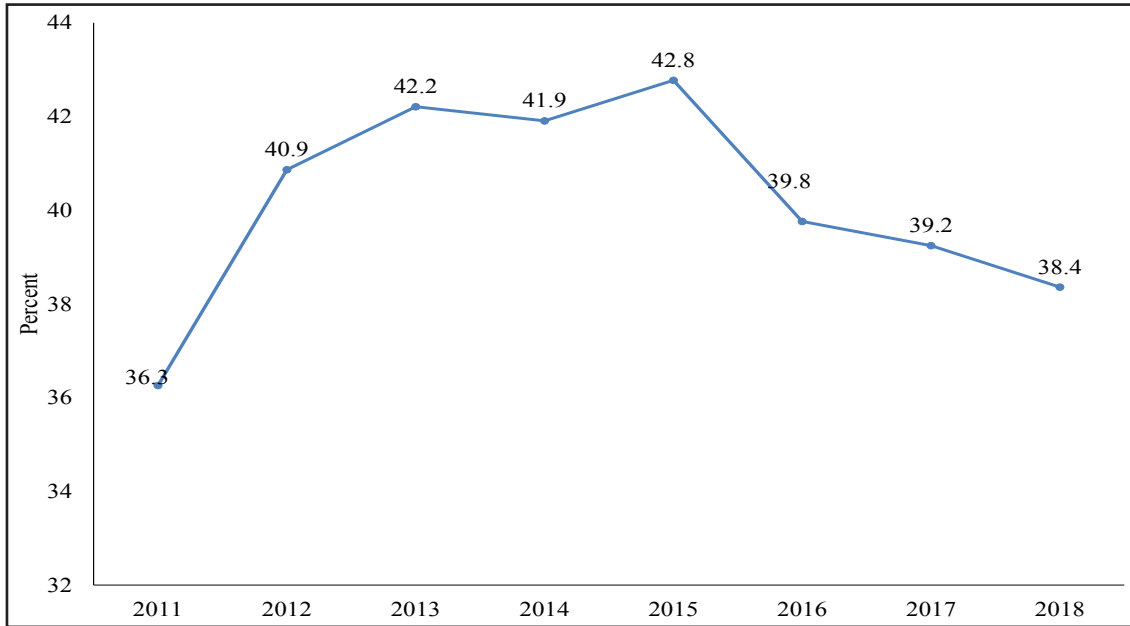
चित्र 20: भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (मिलियन अमरीकी डालर)



स्रोत: आईएमएफ

6.30 तथापि जीडीपी, आईआईपी देनदारियों की प्रतिशतता के रूप में 2011 से 2015 तक पहले बढ़ा था, तभी से कम हो रहा है (चित्र 21)।

**चित्र 21: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल देनदारियाँ**



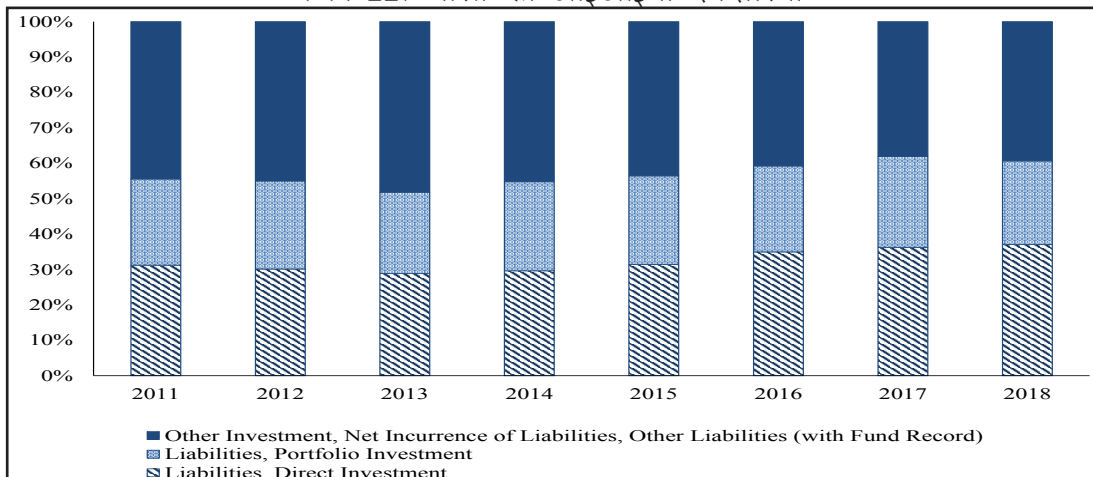
स्रोत: आईएमएफ के आंकड़ों पर आधारित

6.31 आईआईपी विवरण में कुल देनदारियाँ केवल विदेशी ऋण की अपेक्षा विदेशी ऋणग्रस्तता का अधिक व्यापक आंकलन है जैसे कि पहले में निवल इक्विटी अंतर्वाह भी शामिल है जो सीएडी के वित्तपोषण में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि चित्र 22 में दर्शाया गया है कि विदेशी ऋणग्रस्तता में गिरावट 2015 में सामने आई है तथा सीएडी द्वारा उपलब्ध कराए गए

हाल ही के स्तर पर स्थिर रह सकती है जैसे कि जीडीपी की प्रतिशतता जीडीपी के 2.2 से 2.5 प्रतिशत की श्रेणी में रहती है।

6.32 सीएडी के वित्तपोषण के अधिक मात्रा में स्थायी स्रोतों पर निर्भरता को दर्शाते हुए कुल देनदारियों में निवल एफडीआई अंतर्वाह के भाग में 2013 से निरंतर वृद्धि हुई है (चित्र 22)।

**चित्र 22: भारत की आईआईपी देनदारियाँ**



स्रोत: आईएमएफ के आंकड़ों पर आधारित



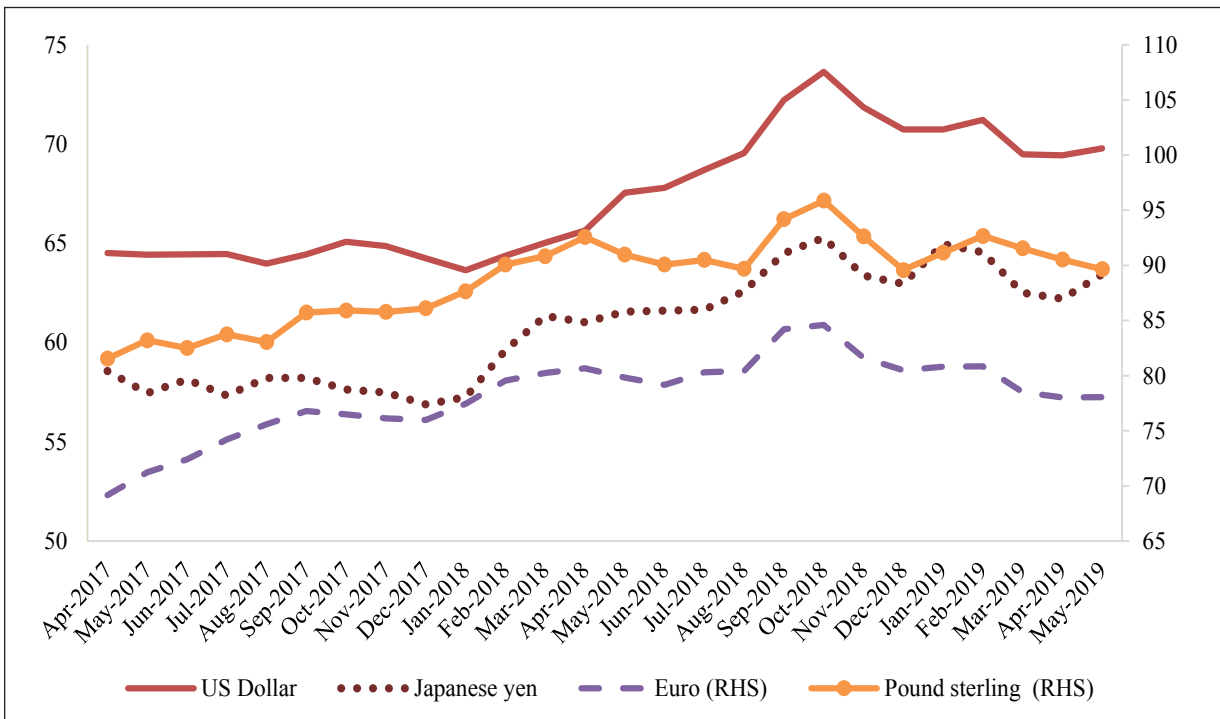
**सांकेतिक तथा वास्तविक विनिमय दर तथा व्यापार स्थिति**

**विनिमय दर**

6.33 वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रुपया न्यूनतम अस्थिर नई बाजार मुद्राओं में से एक था तथा अमरीकी डालर की तुलना में 63.63 से 65.08 के बीच रहा। 2018-19 के दौरान अमरीकी डालर के विरुद्ध भारतीय रुपये की मूल्यहास की प्रवृत्ति रही है तथा मार्च 29, 2019 को 4.1 प्रतिशत से 69.2 प्रति अमरीकी डालर की वसूली करने से पहले 11 अक्टूबर, 2018 को अब तक के इतिहास में 74.4 प्रति अमरीकी डालर (संदर्भ दर) तक पहुंच गया था। वर्ष 2018-19 की पहली छमाही में अमरीकी फेडरल रिजर्व द्वारा संघीय निधि में वृद्धि करने के कारण कठिन वित्तीय परिस्थितियों के साथ कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से सीएडी को व्यापक बनाने से संबंधित मामलों के कारण रुपया कमजोर रहा। तथापि इसके पश्चात सभी प्रमुख केंद्रीय बैंकों में आसान मौद्रिक नीति स्वरूप तथा जोखिम के

प्रतिफल के साथ कच्चे तेल की कीमतों को सुगम बनाने के कारण एफवीआई अंतर्वाह शुरू हुआ तथा 2018-19 की चौथी तिमाही में रुपए को बचाने में मदद की। वर्ष 2018-19 में अमरीकी डालर के सामने रुपये के मूल्य में समस्त गिरावट के होते हुए भी, 2017-18 के विपरीत अन्य प्रमुख मुद्राओं जैसे कि अर्जेन्टीना की पीसो, तुर्की की लीरा, ब्राजील की रियाल और रूस की रूबल से बेहतर निष्पादन किया जिनका अमरीकी डालर के सामने 10 प्रतिशत से अधिक मूल्यहास हुआ। वर्ष 2018-19 में अमरीकी डालर के सामने रुपए के 7.8% अवमूल्यन से अलग इसका अन्य मुख्य मुद्राओं के सामने भी मूल्यहास हुआ। इसका येन के सामने 7.7 प्रतिशत तथा यूरो और प्रत्येक पाउंड स्टर्लिंग (चित्र 23) के सामने 6.8% अवमूल्यन हुआ। वर्ष 2018-19 में विदेशी मुद्रा की एक यूनिट के विपरीत रुपए की विनिमय दर तथा विनिमय बाजार में आरबीआई द्वारा अमरीकी डालर का विक्रय/क्रय अनुलग्नक-IV में दर्शाया गया है।

**चित्र 23: अमरीकी डालर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग तथा जापानी येन के मुकाबले रुपए का संचलन**



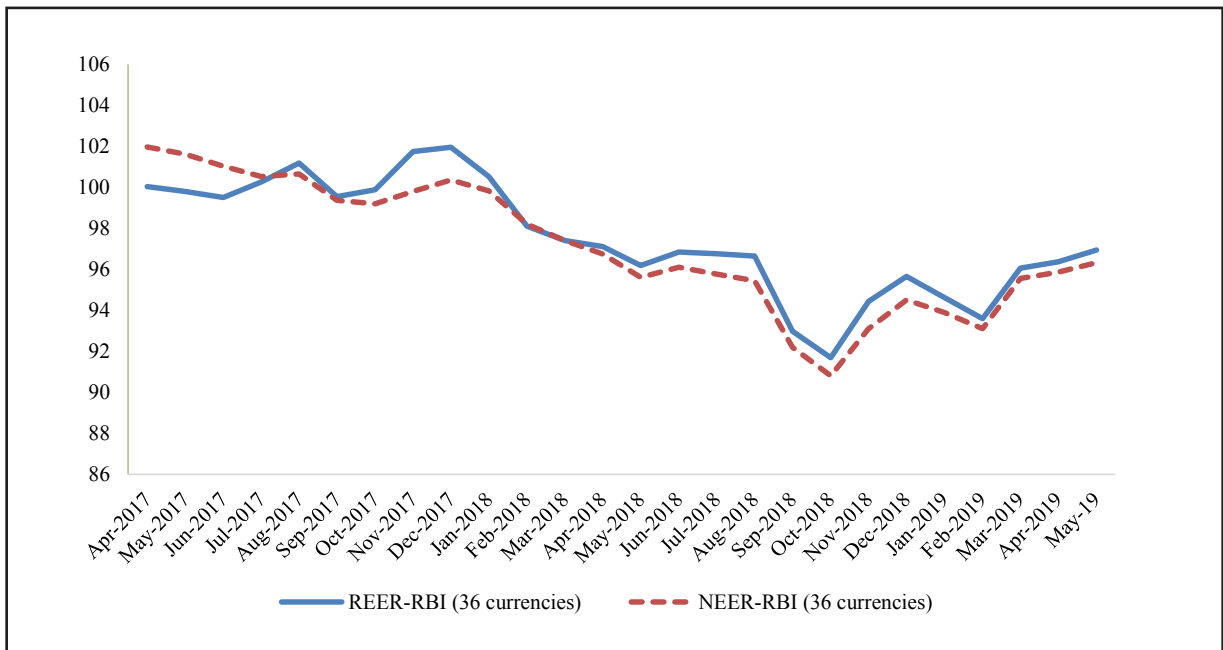
स्रोत: आरबीआई (अमरीकी डालर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो तथा जापानी येन के विपरीत भारतीय रुपए की विनिमय दर-मासिक औसत)।  
टिप्पणी: जापानी येन की विनिमय दर 100 येन प्रति रुपये है।

## एनईईआर तथा आरईईआर

6.34 6 और 36 करेंसी नगण्य प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) (व्यापार आधारित भार) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा 2017-18 में रुपए का क्रमशः 7.1 तथा 5.6% मूल्यहास हुआ। 6 और 36 करेंसी वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) के अनुसार 2018-19 तथा 2017-18 को रुपए का क्रमशः 5.8 प्रतिशत तथा 4.8 प्रतिशत अवमूल्य हुआ

है। तीव्र अवमूल्यन अक्टूबर 2018 में हुआ जैसा कि चित्र 24 में दर्शाया गया है। जिसके पश्चात् रुपए की प्रवृत्ति बदलने के साक्ष्य मिले हैं। इसके लिए मजबूत अर्थव्यवस्था के मूल तत्वों, कच्चे तेल की कीमतों का कम होना, निर्यातकों और बैंकों द्वारा डालर का बेचना जारी रखना, तथा भारतीय शेयर बाजार में वसूली के कारण निवेशक के विश्वास में सुधार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

चित्र 24: आरईईआर, एनईईआर (व्यापार आधारित) में सूचकांकों का संचलन (2017-18=100)



स्रोत: आरबीआई।

## विनिमय दर परिवर्तनशीलता

6.35 निम्नलिखित सारणी 1 माह के अधिकतम और न्यूनतम परिवर्तन की गणना के लिए एक वर्ष में अधिकतम और न्यूनतम मासिक विनिमय दर दर्शाती है। विनिमय दर की अस्थिरता के सूचक के रूप में

मासिक आंकड़ों का प्रयोग करते हुए मानक विचलन की गणना की जाती है। यह दो वर्ष की सापेक्षिक स्थिरता के पश्चात् 2018-19 में रुपये की परिवर्तनशीलता के प्रवाह में क्षणिक परिवर्तन को दर्शाता है।

6.36 चित्र 25 अप्रैल, 2017 से अप्रैल, 2019 के बीच

सारणी 1: रुपया डालर परिवर्तनशीलता

वर्ष	माह-अधिकतम	माह-न्यूनतम	अधिक-न्यून प्रतिशतता परिवर्तन	मानक विचलन
2011-12	43.9	54.2	23.4	3.1
2012-13	50.58	57.22	13.1	1.1
2013-14	53.74	68.36	27.2	3.1

2014-15	58.43	63.75	9.1	1.1
2015-16	62.16	68.78	10.6	1.7
2016-17	64.84	68.72	6.0	0.6
2017-18	63.35	65.76	3.8	0.4
2018-19	64.93	74.39	14.6	2.3

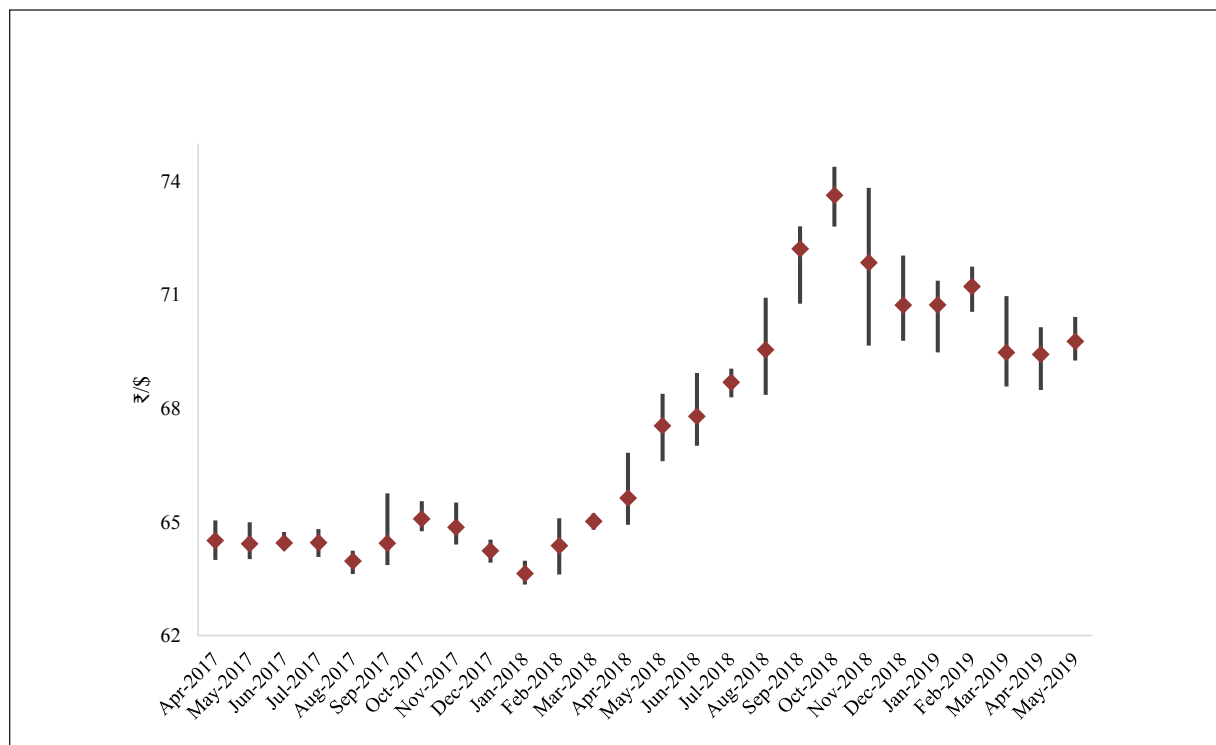
स्रोत: आरबीआई आंकड़ों पर आधारित।

डालर के विपरीत भारतीय रुपए के मासिक उतार-चढ़ावों और औसत को दर्शाता है जहां से यह स्पष्ट होता है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 में रुपया सापेक्षिक

रूप से अधिक अस्थिर हुआ है।

6.37 विनिमय दर परिवर्तनशीलता की सीमा उस मात्रा पर निर्भर करती है जिससे विनिमय दर संचलन का पूर्वानुमान

चित्र 25: विनिमय दर उतार और चढ़ाव



स्रोत: आरबीआई आंकड़ों पर आधारित।

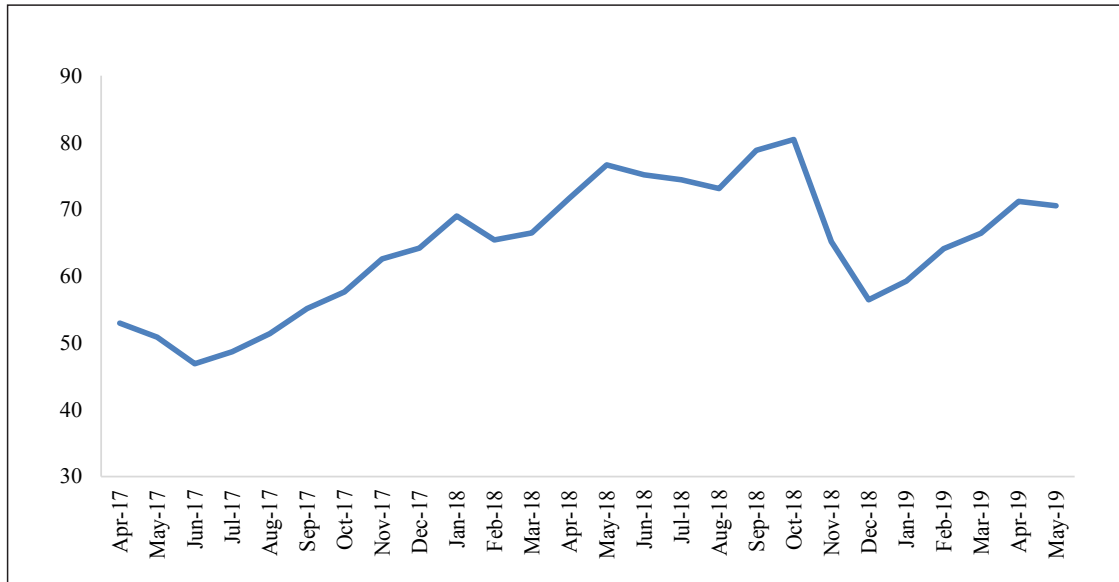
लगाया जा सके। विशेषतः हाल ही के वर्षों में कच्चे तेल की कीमतें और निवल पोर्टफोलियो प्रवाह विनिमय दर संचलन के मुख्य संचालक रहे हैं। इन परिवर्तनशील दरों के संचलन से पूर्वानुमान में मदद मिल सकती है जैसे कि विनिमय दरों में विभिन्नता जिससे परिवर्तनशीलता का बचाव तथा कुछ सीमा तक व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा।

6.38 चित्र 26 अप्रैल 2017 से मई 2019 तक के कच्चे तेल की कीमतों में संचलन को दर्शाता है। वर्ष 2018-19 तेल और गैस उद्योग के लिए मिश्रित सफलता का वर्ष प्रतीत हाता है जिसमें तेल व गैस उद्योगों ने अधिक वैश्विक आपूर्ति, विश्व आर्थिक वृद्धि की धीमीगति के पूर्वानुमान की पृष्ठभूमि के विपरीत

कीमतों में नवम्बर में गिरावट से पहले अपनी कीमतें मजबूत बना ली थी। तथापि दिसम्बर, 2018 से तेल बाजार से ईरान को पूर्णतया बाहर करने की अमरीकी

घोषणा का अनुपालन करके कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई।

चित्र 26: कच्चे तेल की कीमतें ( बिलियन डॉलर )



स्रोत: बेंट कच्चे तेल की कीमतों के लिए विश्व बैंक पिंग शीट आंकड़ों पर आधारित।

6.39 जैसा कि सारणी 1, सारणी 2 में दिया गया है कि मासिक उतार चढ़ाव में परिवर्तन की गणना करने हेतु उच्चतम और न्यूनतम मासिक कीमतों का प्रयोग भी होता है। कीमत में परिवर्तन के सूचक के रूप में मासिक आंकड़ों का प्रयोग करते हुए मानक विचलन की

गणना की जाती है। वर्ष 2014-15 में उच्चतम परिवर्तन रिकार्ड किया गया। मानक विचलन चित्र यह दर्शाते हैं कि 2015-16 की तुलना में 2017-18 और 2018-19 में कच्चे तेल की कीमतें पूर्णतया अस्थिर रहीं।

सारणी 2: कच्चे तेल की कीमतों की अस्थिरता ( बिलियन डॉलर )

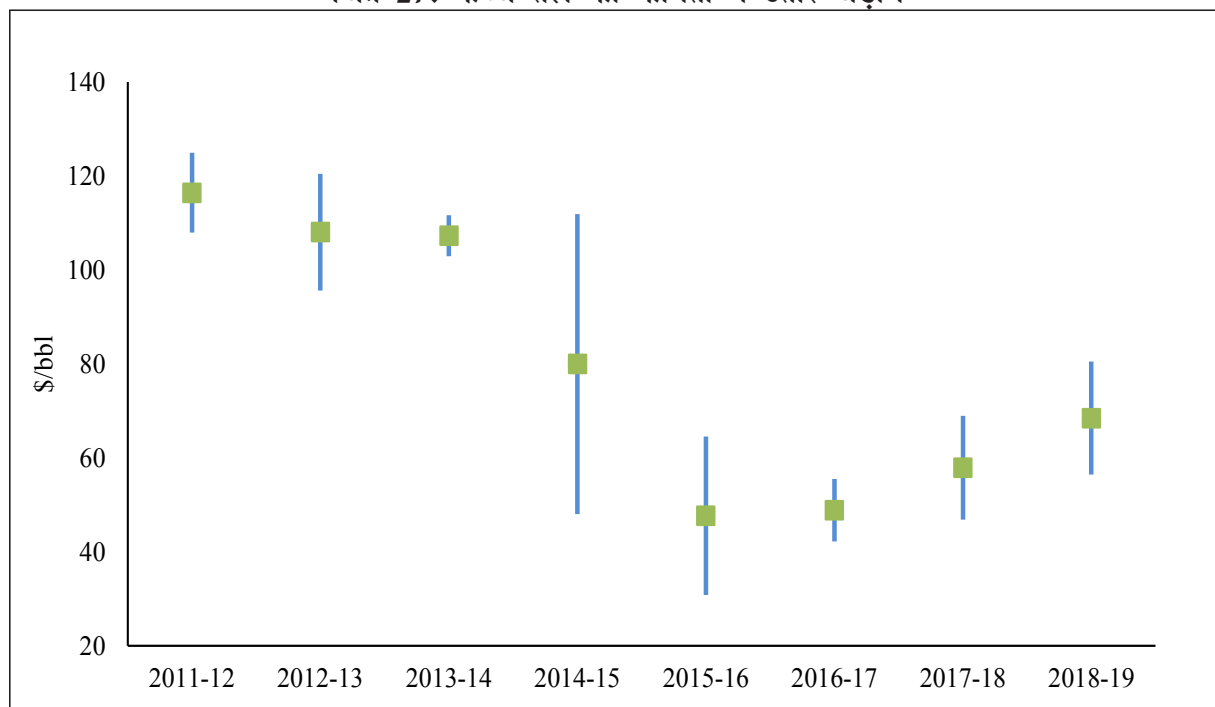
वर्ष	माह-अधिकतम	माह-न्यूनतम	अधिक-न्यून प्रतिशतता परिवर्तन	मानक विचलन
2011-12	124.9	107.9	15.8	5.6
2012-13	120.5	95.6	26.0	6.3
2013-14	111.6	102.9	8.5	3.1
2014-15	111.9	48.1	132.7	23.9
2015-16	64.6	30.8	109.6	11.2
2016-17	55.5	42.3	31.3	4.3
2017-18	69.0	46.9	47.1	7.6
2018-19	80.5	56.5	42.5	7.7

स्रोत: बेंट कच्चे तेल की कीमतों के लिए विश्व बैंक पिंग शीट आंकड़ों पर आधारित।

6.40 वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और औसत चित्र 27 में दर्शाए गए हैं। भारत में उतार उच्च वास्तविक जीडीपी

वृद्धि से तथा चढ़ाव निम्न वास्तविक जीडीपी वृद्धि के अनुरूप होता है।

चित्र 27: कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव



स्रोत: बेंट कच्चे तेल की कीमतों के लिए विश्व बैंक की पिंक शीट पर आधारित।

6.41 सारणी 3 में 2011-12 से 2018-19 की अवधि के लिए उतार-चढ़ावों के बीच अस्थिरता की गणना के लिए मासिक निवल विदेशी विशेष निवेश (एफपीआई) आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। मासिक आंकड़ों का

प्रयोग करके मानक विचलन की गणना की गई है। यह इंगित करता है कि निवल एफपीआई में 2013-14 में अधिकतम परिवर्तन हुए इसके पश्चात् 2018-19 में यह अपेक्षाकृत स्थिर रही।

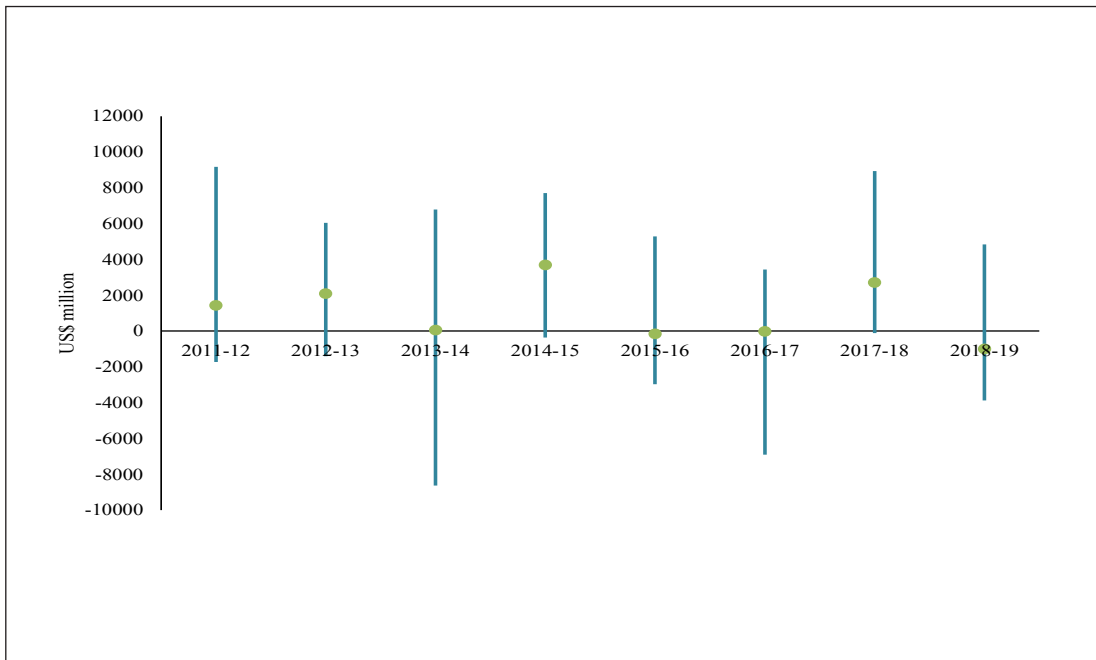
सारणी 3: निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) अस्थिरता

Year	Month-high	Month-low	High-low % change	Standard deviation
2011-12	9170	-1734	-628.84	3250.93
2012-13	6042	-1409	-528.81	2395.78
2013-14	6782	-8628	-178.60	3904.63
2014-15	7701	-361	-2233.24	2554.61
2015-16	5288	-2973	-277.87	2847.21
2016-17	3429	-6911	-149.62	2976.37
2017-18	8935	-120	-7545.83	2720.91
2018-19	4831	-3882	-224.45	2610.56

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों पर आधारित।

6.42 चित्र 28, 2011-12 से 2018-19 तक निवल एफडीआई प्रवाह के उतार-चढ़ाव और औसत प्रदर्शित कर रहा है।

चित्र 28: निवल विदेशी पोर्टफोलियों निवेश में उतार और चढ़ाव



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों पर आधारित।

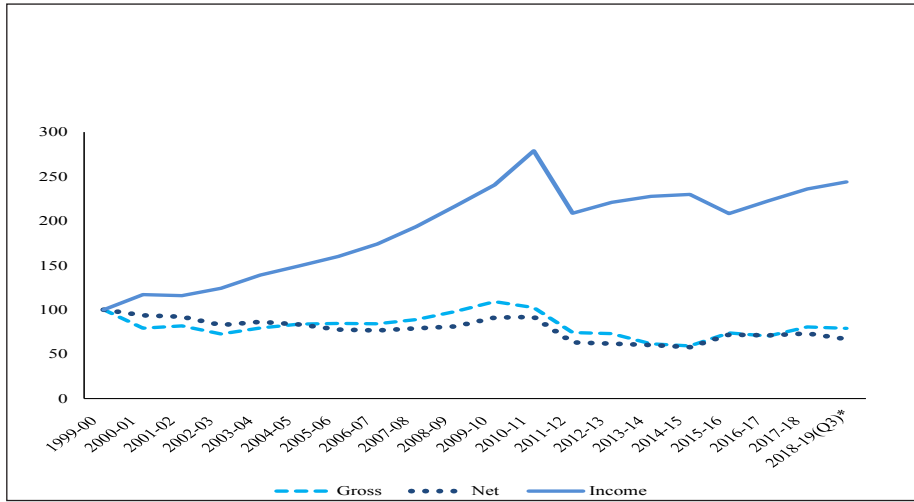
6.43 यह स्पष्ट है कि विनिमय दर परिवर्तनों में गतिविधियां कच्चे तेल के मूल्य और निवल एफडीआई प्रवाह में परिवर्तनों से गहन रूप से संबद्ध हैं। वैश्विक और घरेलू दोनों कारकों के कारण 2018-19 में रुपया अस्थिर रहा है जिसमें कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि, अनियमित व्यापार संतुलन, डालर का सुदृढ़ीकरण तथा सतत एफडीआई बाह्य प्रवाह शामिल हैं। रुपये पर प्रभाव डालने वाले अतिरिक्त कारकों में अमरीका और चीन के बीच व्यापार युद्ध, ईरान पर अमरीका के प्रतिबंध तथा अमरीकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में बढ़ोतरी शामिल है।

### व्यापार की शर्तें

6.44 जबकि आरईईआर का हास यह इंगित करता है कि भारत के निर्यातों को अधिक प्रतिस्पर्धात्मकता हो जाना चाहिए था परंतु आरईईआर का मूल्यांकन कम प्रतिस्पर्धात्मक निर्माता को दर्शाता है। निर्यातों की मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता इस बात को देखकर बेहतर रूप से आंकी जा सकती है कि एक समय अवधि में व्यापार की शर्तें कैसी रही हैं। वस्तु अथवा किसी देश के व्यापार की निवल शर्तें आधारवर्ष के सापेक्ष मापे गए निर्यात के ईकाई भाव (मूल्य) तथा आयात के संगत

ईकाई (मूल्य) का अनुपात है। अगर यह अनुपात बढ़ता है, तो यह दर्शाता है कि देश, जो निर्यातों की प्रत्येक इकाई के लिए आयातों का विनिमय करता है, तुलनात्मक रूप से अधिक प्राप्त कर रहा है और यदि यह अनुपात घटता है तो देश तुलनात्मकरूप से कम प्राप्त कर रहा है। व्यापार घातांकों के लिए सामान्यरूप से प्रयोग की जाने वाली दो अन्य शर्तें व्यापार की सकल शर्तें और व्यापार की आय संबंधी शर्तें हैं। व्यापार की सकल शर्तें (जीजीटी) किसी देश के आयातों एवं निर्यातों की कुल मात्रा का अनुपात है। व्यापार की आय संबंधी शर्तें (आईटीटी) आयातों के ईकाई भाव (मूल्य) द्वारा विभाजित निर्यातों का मूल्य है जो यह दर्शाता है कि आयातों के संबंध में किसी देश की क्रय शक्ति कितनी बेहतर अथवा खराब हो गयी है। चित्र 29 इन तीन घातांकों में 1999-2000 से 2018-19 गतिविधि का आलेख प्रस्तुत करती है। 2017-18 की तुलना में, भारत की व्यापार की निवल शर्तें (एलटीटी) तथा जीटीटी 2018-19 के दौरान क्रमशः 8.9% तथा 2.1% कम हुई है। जबकि व्यापार की आय संबंधी शर्तें 3.4% बढ़ी हैं। तथापि व्यापार की शर्तों के सभी घातांक 2015-16 से ऊपर उठते हुए हैं।

चित्र 29: व्यापार की शर्तें (आधार वर्ष 1999-2000)

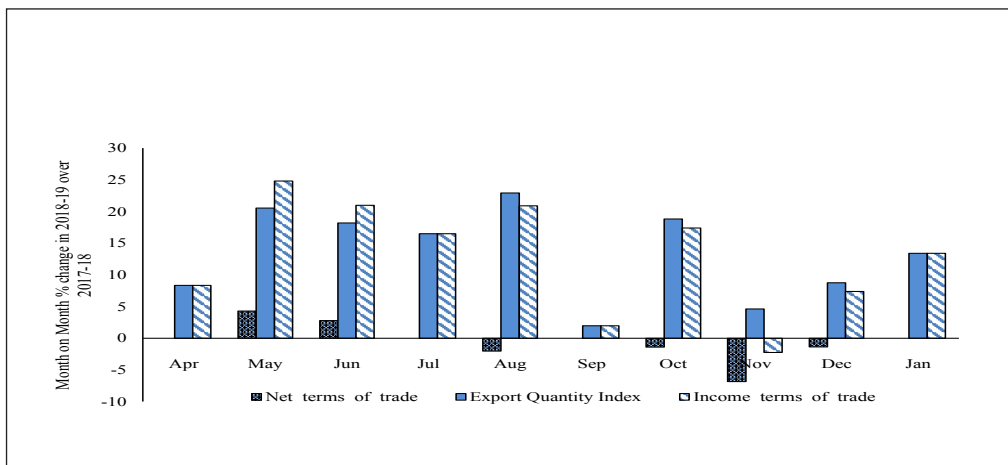


स्रोत: जीडीसी आई एंड एस, कोलकाता  
 \* 2018-19 की तीसरी तिमाही तक के आंकड़े उपलब्ध है

6.45 विकासशील देशों के लिए आईटीटी सर्वाधिक संगत टीओटी संकेतक रही है क्योंकि ये आयात की अपनी क्षमता में परिवर्तनों के बारे में अधिक चिंतित है। विशेषरूप से तब जब ये वस्तु आयातों पर ज्यादा निर्भर होती है जैसे भारत कच्चे तेल के आयातों पर निर्भर रहा है। वर्ष 2000 से आई टी टी के बढ़ते हुए रुझान के साथ, भारत आयात के संदर्भ में अपनी क्रयशक्ति लगातार बढ़ा रहा है। यह समझने के लिए कि आई टी टी में कौन परिवर्तन ला रहा है, चित्र 30 अप्रैल-जनवरी, 2018-19 के लिए एन टी टी में परिवर्तनों और निर्यात मात्रा सूचकांक के संदर्भ में आई आई टी में परिवर्तन को विघटित करता है। चित्र यह

दर्शाता है कि आई टी टी में परिवर्तन, निर्यात और आयातों के सापेक्ष इकाई मूल्यों में परिवर्तन की अपेक्षा निर्यात की मात्रा में परिवर्तनों द्वारा अधिक निकटता से पता लगाए गए हैं। चूंकि निर्यात की मात्रा में बढ़ोतरी विश्व उत्पाद की वृद्धि में बढ़ोतरी से प्रत्यक्ष रूप में सहसंबंधित है, अतः विश्व उत्पाद में मंदी ने 2018-19 के अप्रैल-जनवरी के दौरान आयात की क्षमता को कम कर दिया है जबकि भारत का आयात मूल्य देश के निर्यात मूल्यों की अपेक्षा तेजी से घटा है। शायद यह देश के लिए सकारात्मक आई टी टी प्रभाव उत्पन्न करने के लिए विश्व उत्पाद की मंदी को प्रति संतुलित करने हेतु आयात मूल्यों में अधिक गिरावट लाएगा।

चित्र 30: व्यापार की आय संबंधी शर्तों परिवर्तन का अघटन

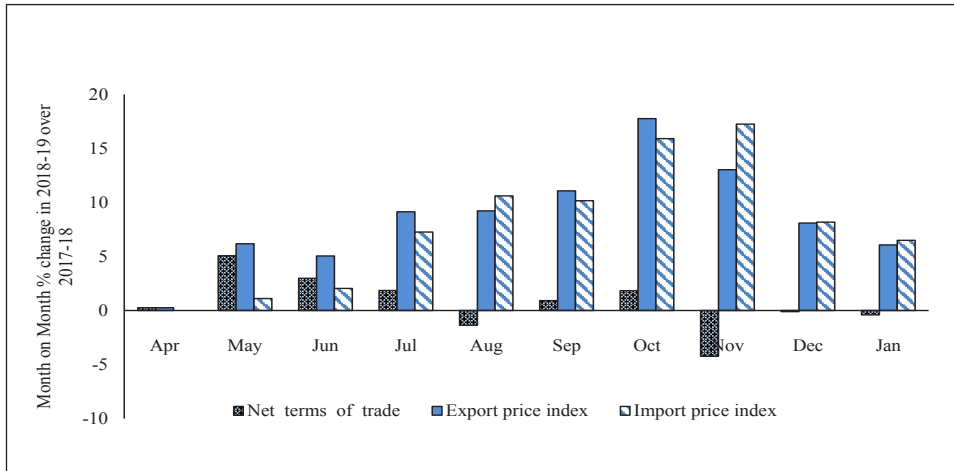


स्रोत: डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों पर आधारित  
 टिप्पणी: जनवरी 2019 तक के आंकड़े उपलब्ध है

6.46 चित्र 31 यह दर्शाता है कि दिसंबर, 2018 में आयात मूल्य सूचकांक में कमी को जनवरी, 2019

के स्तर तक पहुंचना है, जिससे आयात की क्षमता में कमी करने के लिए गिरावट बलवती हो सकती है।

चित्र 31: 2018-19 में व्यापार की निवल शर्तों में परिवर्तन का अपघटन



स्रोत: डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों पर आधारित  
टिप्पणी: जनवरी, 2019 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं

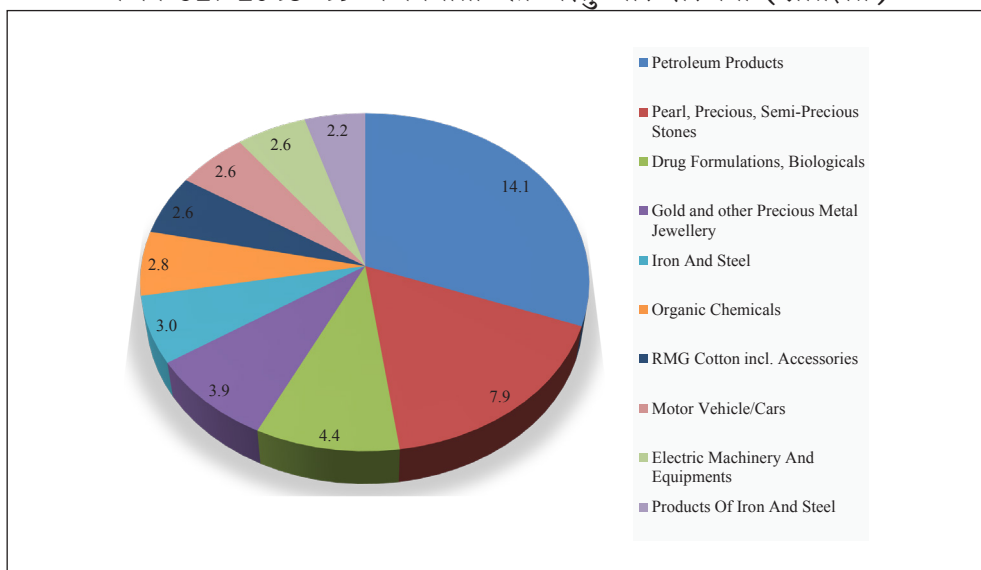
### व्यापार की संरचना

#### 2018-19 में विनिर्मित मुख्य उत्पाद

6.47 वर्ष 2018-19, पेट्रोलियम उत्पाद देश के मूल्य के हिसाब से निर्यात अंश में 14.1% हिस्से के साथ सर्वाधिक बड़ी वस्तु बनी रही। अन्य मुख्य निर्यातों में मोती, मूल्यवान अर्ध-मूल्यवान पत्थर तथा स्वर्ण और

औषधी से तैयार वस्तुओं, जैविक वस्तुओं के अलावा अन्य मूल्यवान धातु के आभूषण शामिल हैं (चित्र 32)। तथापि, जैविक रसायनों का निर्यात सबसे ज्यादा हुआ था जो 2018-19 में निर्यात का 30.6% था।

चित्र 32: 2018-19 में निर्यातों की वस्तु-वार संरचना (प्रतिशत)



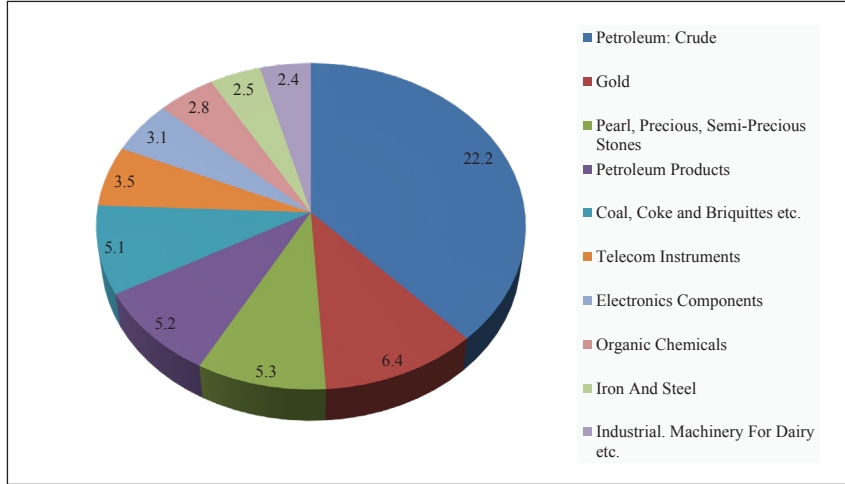
स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता।



6.48 2018-19 के आयात अंश में, सर्वाधिक हिस्सा पेट्रोलियम: कच्चा माल का था जो 22.2 प्रतिशत था तथा इसके बाद स्वर्ण और अर्ध-मूल्यवान धातु के आभूषणों का हिस्सा था जो 6.4 प्रतिशत तथा इसके बाद मोती/अर्धमूल्यवान पत्थरों का हिस्सा था जो 5.3 प्रतिशत था (चित्र 33)। तथापि, स्वर्ण और मोतियों की वृद्धि दर (मूल्यवान और अर्ध-मूल्यवान पत्थरों

सहित) 2018-19 में कम हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक तेजी से बढ़े हैं जो 2018-19 में 54.6% रहे, इसके बाद पेट्रोलियम, कच्चा लौह और इस्पात का स्थान रहा। दस बड़ी वस्तुओं के आयातों/निर्यातों, 2017-18 और 2018-19 (पी) में उनकी वृद्धि दर और प्रतिशत हिस्से को अनुबंध-VI में दर्शाया गया है।

चित्र 33: 2018-19 में आयातों की वस्तु-वार संरचना पी (प्रतिशत)



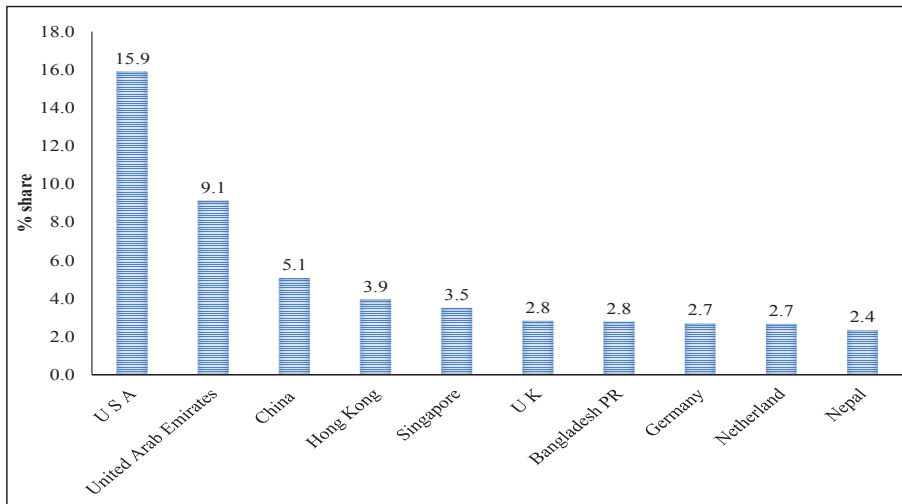
स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता

### 2018-19 में व्यापार में मुख्य भागीदार

6.49 संयुक्त राज्य अमरीका भारत का सर्वाधिक निर्यातोन्मुख देश बना हुआ है जो 2018-19 में भारत के निर्यात का (मूल्य के अर्थ में) 16% अंश के लिए

उत्तरदायी है, इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, चीन और हांगकांग आते हैं (चित्र 34)। तथापि, 2018-19 में नीदरलैंड (40.7 प्रतिशत) को किए गए भारतीय निर्यात में बढ़ोतरी सर्वाधिक थी। इसके बाद चीन (25.6 प्रतिशत) और नेपाल (17.4 प्रतिशत) का स्थान रहा।

चित्र 34: 2018-19 में भारत के निर्यातोन्मुखी शीर्ष 10 देश

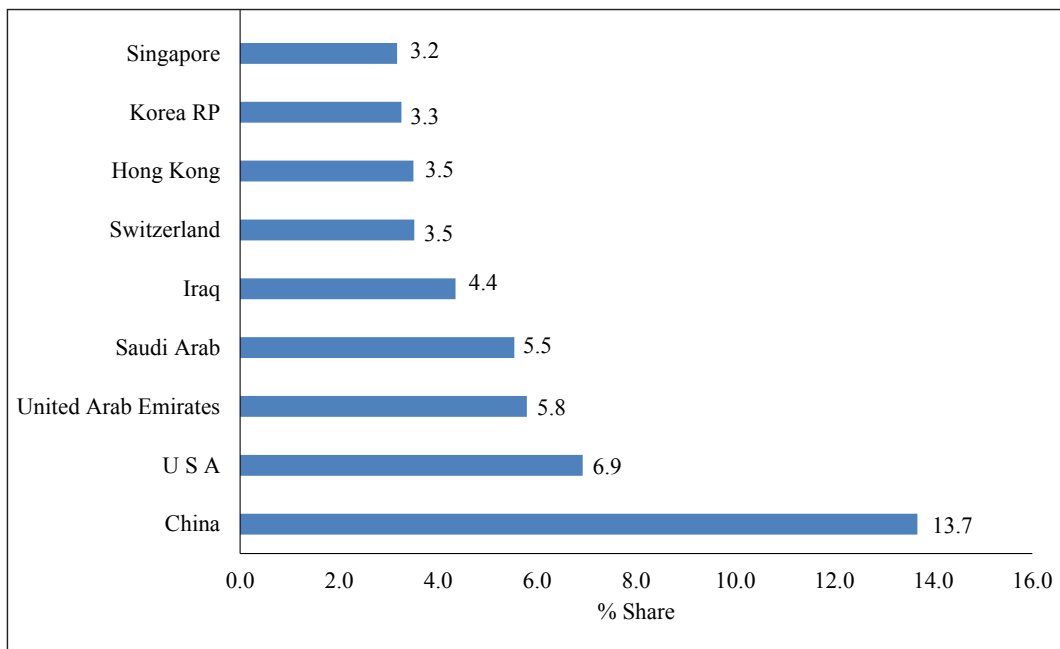


स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता।

6.50 चीन भारत के आयातों का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है जो 2018-19 में कुल आयातित मूल्य के 13.7% के लिए जिम्मेदार है। अमरीका, यूई और सऊदी अरब अन्य महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिससे भारत आयात करता है (चित्र 35)। (वृद्धि दर के अर्थ में 2018-19 की वृद्धि में सिंगापुर से आयात सर्वाधिक रहा है जोकि हांगकांग (68.5 प्रतिशत) तथा यू ए ई

(37.0 प्रतिशत) के बाद 118.1% है। यद्यपि, चीन भारत का सबसे बड़ा निर्यातक बना हुआ है, परंतु चीन से भारत का आयात 2017-18 में 76.4 बिलियन अमरीकी डालर से गिरकर 2018-19 में 70.3 बिलियन हो गया है जिसने ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की है। 2017-18 और 2018-19 में भारत शीर्ष 10 निर्यातोन्मुखी देश और आयात के स्रोत अनुबंध-VII में दर्शाए गए हैं।

चित्र 35: 2018-19 में भारत के शीर्ष 10 आयात स्रोत



स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता।

## व्यापार नीति

6.51 सभी मुख्य क्षेत्रीय समूहों के साथ भारत की द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्थाएं हैं। यूरोप में, यह यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) का हिस्सा है जिसमें स्विटजरलैंड, नार्वे, आईसलैंड और लिक्टेनस्टाइन शामिल हैं। 2018-19 में, भारत ने ईएफटीए के साथ निर्यात व आयात किया है जो क्रमशः 1534.00 मिलियन अमरीकी डालर और 18.076.88 मिलियन अमरीकी डालर था।

6.52 सार्क देशों में, भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्था है और दोनों देश द्विपक्षीय आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) करने की संभावना

तलाश रहे हैं। वर्ष 2018-19 में, भारत ने बांग्लादेश से निर्यात व आयात किया है जो क्रमशः 8,933.47 मिलियन अमरीकी डालर और 1043.03 मिलियन अमरीकी डालर था। अधिमाल व्यापार करार (पीटीए) करने के लिए वार्ता चल रही है। व्यापार हेतु भारत नेपाल संधि के लिए समीक्षा बैठकें जारी हैं। श्रीलंका के साथ, भारत ने भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार किया हुआ है जिसके अंतर्गत कुछ उत्पादों को छोड़कर लगभग सभी उत्पादों के लिए शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान की जाती है। भारत श्रीलंका के साथ एक नए आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग करार (ईटीसीए) पर बातचीत कर रहा है। 2018-19 में, भारत ने श्रीलंका के साथ

निर्यात व आयात किया है जो क्रमशः 4,707.14 मिलियन अमरीकी डालर और 1473.10 मिलियन अमरीकी डालर था।

6.53 भारत और आसियान, आसियान भारत वस्तु व्यापार करार (एआईटीआरजीए) की समीक्षा की संभावना से संबंधित प्रारंभिक प्रस्तावों की जांच प्रारंभ करने के लिए सहमत हो गये हैं। आसियान के भीतर, भारत का सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) है। 2018-19 में, भारत ने आसियान गुट के साथ निर्यात व आयात किया है जो क्रमशः 37,460.34 मिलियन अमरीकी डालर और 59,293.36 मिलियन अमरीकी डालर था।

6.54 लैटिन अमरीकी देशों में, भारत का एमईआरसीओएसयूआर (अर्जेटीना, ब्राजील, पैरागुए और यूरागुए) और चीली के साथ अधिमान व्यापार करार (पीटीए) है। कोलंबिया के साथ भी पीटी की संभावनाएं खोजी जा रही हैं। भारत पेरू और इक्वाडोर के साथ व्यापार संबंधी करार पर बातचीत कर रहा है। स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल, जार्जिया के साथ मुक्त व्यापार करार (एफटीए) और यूरोपियाई आर्थिक संघ (ईईईयू) के साथ पीटीए पर बातचीत चल रही है। 2018-19 में, भारत ने एमईआरसीओएसयूआर गुट के साथ निर्यात व आयात किया है जो क्रमशः 4,705.08 मिलियन अमरीकी डालर और 6,425.35 मिलियन अमरीकी डालर था।

6.55 उत्तरी अमरीका मुक्त व्यापार करार (नाफ्टा) के अंतर्गत, भारत कनाडा व्यापक आर्थिक नीति करार (सीईपीए) पर बातचीत चल रही है। भारत आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भी द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईजीए) पर बातचीत कर रहा है। मारीशस के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग और सहभागिता करार (सीईसीपीए) तथा इजरायल के साथ एफटीए पर बातचीत चल रही है। द्विपक्षीय व्यापार करारों की प्रगति को दर्शाने वाली सारणी अनुबंध-VIII पर देखी जा सकती है।

6.56 भारत ने विभिन्न देशों/देश समूहों के साथ 28 द्विपक्षीय/बहुपक्षीय व्यापार करार हस्ताक्षरित किए हैं।

वर्ष 2018-19 में भारत ने उन देशों के साथ 121.7 बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात किया था जिसके साथ इसके व्यापार करार थे और वह सभी देशों के साथ किए गए भारत के निर्यात का 36.9 प्रतिशत है। इसी प्रकार, इसी वर्ष में, भारत उन देशों से 266.9 बिलियन अमरीकी डालर का आयात किया था जिसके साथ इसके व्यापार करार थे और वह सभी देशों से किए गए भारत के आयात का 52.0 प्रतिशत है।

## व्यापार सुगमता

6.57 भारत ने अप्रैल, 2016 में व्यापार सुगमता संबंधी डब्ल्यूटीओ करार की अभिपुष्टि की थी और तदनुसार भारत के मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय व्यापार सुगमता समिति (एनसीओएफ) गठित की थी। इसके अतिरिक्त, भारत की अधिसूचित सुगमता प्रतिबद्धताओं के समग्र कार्यान्वयन को समन्वित करने के लिए वाणिज्य सचिव और राजस्व सचिव की सहअध्यक्षता में एक संचालन समिति गठित की गई।

6.58 इसके बाद, एनसीटीएफ ने आयातों ओर निर्यातों की ऊंची लागत को कम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है ताकि वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ हमारे सीमा पार व्यापार को समेकित किया जा सके। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित हैं:--

- i. सभी आयात संबंधी औपचारिकताओं जैसे जांच, नमूने एकत्र करना, स्वीकृति आदि को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली की स्थापना जिसमें सिंगल ऑनलाइन राष्ट्रीय पोर्टल के जरिए बहुत एजेंसियां शामिल हैं।
- ii. सीमा पर स्वीकृति संबंधी विभिन्न गतिविधियों के लिए शुल्क और प्रभारों का सरलीकरण।
- iii. 'ई-संचित' परियोजना के जरिए आयात/निर्यात दस्तावेजों को बिना कागज के दायर करना; और
- iv. पहुंच को सुगम बनाने के लिए संसाधन सूचना अर्थात् आयात/निर्यात की पद्धतियां, कानून और विनियमों आदि का ऑनलाइन प्रकाशन।

6.59 व्यापार सुगमता के सतत प्रयासों से सीमापार व्यापार संकेतक में भारत के कार्य निष्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है जो 2017 में 146 से 2018 में 80 हो गया। इसके अतिरिक्त, इन पहलों ने देश में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के मामले में समग्र सुधार हेतु योगदान दिया है, जिसे विश्व बैंक ने भी माना है।

### व्यापार संबंधी संभारिकी

6.60 भारतीय संभारिकी क्षेत्र भारी वृद्धि की ओर अग्रसर है। घरेलू रेटिंग एजेंसी आईसीआर के अनुसार, भारतीय संभारिकी क्षेत्र मध्यम अवधि के दौरान 8-10 प्रतिशत की दर से बढ़ना अपेक्षित है। यह 7.8 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर में सुधार है। जिसपर पिछले पांच वर्षों के दौरान उद्योग में बढ़ोतरी हुई। भारत का संभारिकी उद्योग फिलहाल लगभग 215 बिलियन अमरीकी डालर आंका गया है।

6.61 पिछले कुछ वर्षों में इस उद्योग में महत्वपूर्ण विकास हुआ है जो वैश्विक रैंकिंग में प्रदर्शित है। विश्व बैंक के 2016 संभारिकी निष्पादन सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग के अनुसार, भारत समग्र संभारिकी निष्पादन के अर्थ में 2014 में 54वीं रैंक से उछलकर 2016 में 35वीं रैंक पर आ गया है। 2018 में भारत का रैंक 44 वां था। विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की है 2022 तक संभारिकी क्षेत्र सबसे बड़ा रोजगार सृजक क्षेत्र हो सकता है। यह क्षेत्र फिलहाल देश में 72 करोड़ से ज्यादा रोजगार प्रदान करता है।

6.62 भारत सरकार ने राष्ट्रीय संभारिकी नीति का मसौदा तैयार किया है जिसके लिए राष्ट्रीय संभारिकी कार्रवाई योजना विकसित की जा रही है इसके प्रमुख उद्देश्य संपूर्ण समेकित, प्रभावपूर्ण, दक्ष, विश्वसनीय तथा लागत प्रभावी संभारिकी तंत्र, इस श्रेणी के बेहतर प्रयोग करना और संसाधित एवं कौशल प्राप्त श्रम शक्ति के जरिए देश की आर्थिक वृद्धि तथा व्यापार प्रतियोगितात्मकता को आगे ले जाना है। विभिन्न संभारिक योजना शुरू की गई है जो कि नीचे दी गई हैं।

### संभारिकी से संबंधित योजनाएं

- i. सरकार ने बहुत से महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं जैसे भारतमाला योजना, सागरमाला योजना और डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य देश में बढ़ रही संभारिकी की मांग को पूरा करने के लिए अवसंरचना का विकास करना तथा परिवहन की अधिक लागत प्रभावी प्रणालियों से संबंधित विधा परिवर्तन करना है।
- ii. विकास के लिए 111 जल मार्गों का पता लगाया गया है।
- iii. चुनी हुई संभारिकी गतिविधियों जैसे भांडागार, प्रशीतन श्रृंखलाएं, मल्टी मॉडल संभारिकी पार्कों तथा स्लरी पाइप लाइनों, को अवसंरचना का दर्जा दिया गया है।
- iv. प्रशीतन श्रृंखलाओं तथा पैक हाऊस को विकसित करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।

6.63 भारतीय संभारिकी उद्योग एक उदीयमान क्षेत्र है और मांग एवं आपूर्ति दोनों के लिए बहुत से कारक हैं जो इस क्षेत्र को चला रहे हैं। मांग क्षेत्र में जीएसटी के बाद ट्रक के वापस आने के समय में कमी संभारिकी/विकास के लिए एक मुख्य अभिप्रेरक है क्योंकि यह औद्योगिक उत्पादन को भी बढ़ाता है। आपूर्ति क्षेत्र में, भांडागार जैसी गैर जरूरी गतिविधियों का बाह्य स्रोत व परिवहन की दक्षता को सुधारने पर ध्यान देने के लिए मुख्य सहभागियों की व्यवस्था कर रहा है। बड़े भांडागारों का ऑटोमेशन भी संभारिकी क्षेत्र की दक्षता को बढ़ा रहा है।

6.64 बोवरसॉक्स, कैलेनटोन और रोड्रिग्यूस के अनुसार स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में भारत की संभारिकी लागत 1997 में 15.4% और 2000 में 17% थी। आर्मस्ट्रांग एंड एसोसिएट्स (अक्टूबर, 2017) द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय बाजार अनुसंधान के अनुसार, स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में भारत की संभारिकी लागत 13% आंकी गई है। 2016 को संदर्भ वर्ष मानते हुए, शेष विश्व से भारत की तुलना सारणी 4 में की गई है:-

## सारणी 4: भारत तथा शेष विश्व की संभारिकी लागत (संदर्भ वर्ष = 2016)

2016 तुलनात्मक विश्लेषण	संभारिकी लागत ** ( बिलियन अमरीकी डालर )	संभारिकी % स.घ.उ.
भारत	293.1	12.80
ब्राजील	208.6	11.62
चीन	1626.7	14.50
अमरीका	1522.7	8.14
विश्व	8226.3	10.86

स्रोत: \*\* आर्मस्ट्रॉंग एंड एसोसिएट्स, अक्टूबर 2017

6.65 वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बनने हेतु संभारिकी लागत को इस श्रेणी में उत्तम वैश्विक मानकों के साथ जीडीपी के अनुमानित वर्तमान स्तर 13-14% से 10% तक नीचे लाना भारत के लिए अति आवश्यक है।

### डॉपिंगरोधी और सुरक्षा उपाय

6.66 देश में माल की डॉपिंग, घरेलू उद्योग में हानि, तथा घरेलू उद्योग के संबंध में डॉपिंग और हानि के बीच अनियमित संपर्क के प्रथमदृष्टया साहस के साथ घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए आवेदनों के आधार पर, भारत डॉपिंगरोधी अन्वेषण करवाता है। इन अन्वेषणों में अन्य देशों के साथ-साथ चीन, हांगकांग, कोरिया, जर्मनी, ई यू, अमरीका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, ब्राजील शामिल हैं।

6.67 1.4.2018 से 31.3.2019 की अवधि के दौरान, डीजीटीआर ने 24 डॉपिंगरोधी (नए एवं समीक्षा दोनों) अन्वेषण प्रारंभ किए तथा 50 डॉपिंगरोधी अन्वेषणों में अंतिम निष्कर्ष जारी किए। वर्ष 2018-19 के दौरान ए डीजीटीआर ने 5 प्रतिकारी शुल्क अन्वेषण प्रारंभ किए और 2 सीवीडी मामलों में अंतिम निष्कर्ष जारी किए। वर्ष 2018-19 के दौरान एक सुरक्षा उपाय अन्वेषण को भी अंतिम रूप दिया गया था। डीजीटीआर, उद्योग की सुविधा के लिए तथा विभिन्न हितधारकों को

डब्ल्यूटीओ रूपरेखा के अंतर्गत उपलब्ध व्यापार संबंधी उपाय प्रदान करने हेतु डीजीएडी को समर्थ बनाने के लिए डॉपिंगरोधी/प्रतिकारी/प्रवंचना विरोधी अन्वेषणों से संबंधित आवेदनों, सूचना, प्रस्तुतियों, पुनस्तरो, के आनलाइन प्रस्तुतिकरण हेतु एक वेब एप्लीकेशन भी विकसित कर रहा है।

### दृष्टिकोण

6.68 डब्ल्यूईओ, अप्रैल, 2019 ने 2019 की दूसरी छमाही में विश्व उत्पाद में तेजी का पूर्वानुमान लगाया है। इस संबंध में प्रमुख अनुमान अग्रणी देशों में सतत उदार मौद्रिक नीति रूख और चीन में राजकोषीय तेजी तथा अमरीका और चीन के बीच व्यापारिक तनावों में कमी है। कच्चे तेल के मूल्यों में बढ़ोतरी पर दबाव हो सकता है क्योंकि विश्व उत्पाद में बढ़ोतरी होना अभी बाकी है यद्यपि यह भारत पर प्रभाव नहीं डालेगी क्योंकि विश्व उत्पाद में बढ़ोतरी भारत के निर्यातों पर अनुकूल प्रभाव डालेगी जिसे विश्व व्यापार में वृद्धि से अलग नहीं किया गया है। सरकारी नीतियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एफडीआई अंतर्वाहों से प्रतिबंधों को और अधिक उठा दें जिससे चालू खाता घाटा के वित्तपोषण करने वाले साधनों के स्थायित्व का बढ़ाना जारी रहेगा। यदि अर्थव्यवस्था में खपत कम होती है तो निवेश और निर्यात में वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था

### अध्याय पर एक नजर

- डब्ल्यू टी ओ के अनुसार, नए तथा प्रतिकारात्मक टैरिफ उपायों के प्रारंभ होने, बढ़ता हुआ अमरीका-चीन व्यापार संबंधी तनाव, वैश्विक आर्थिक वृद्धि में गिरावट और वित्तीय बाजारों में आस्थिरता के बाद 2018 में विश्वव्यापार में वृद्धि 3 प्रतिशत हुई है, जो 2017 की 4.6 प्रतिशत की वृद्धि दर से काफी कम है।
- भारत के भुगतान क्षेत्र में स्थिति ने कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से वृद्धि से होने वाले उच्च चालू खाता घाटा (सीएडी) के कारण 2018-19 की पहली छमाही के दौरान अवनति के कुछ संकेत दिए हैं। तथापि 2018-19 की तीसरी तिमाही में सीएडी काफी दर तक कम हो गया क्योंकि नवंबर और दिसंबर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें अनुवर्ती रूप से कम हो गयीं। सीएडी का अधिक होना मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें (इंडियन बास्केट) में वृद्धि होने से उच्च व्यापार घाटे के कारण था।
- वाणिज्यिक निर्यात और आयात की वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 में गिरी है, जिसका कारण अन्य कारकों के साथ-साथ, 2018-19 में कम घरेलू जीडीपी वृद्धि के साथ-साथ विश्व उत्पाद और व्यापार में कम वृद्धि मानी जा सकती है।
- वाणिज्यिक व्यापार घाटा के वित्तपोषण में निवल सेवाओं का योगदान 2016-17 में 62.2 प्रतिशत से घट कर 2018-19 में 43.7 प्रतिशत हो गया जो फिलहाल समय में सेवा निर्मातों के न्यून निष्पादन को दर्शाता है।
- वर्ष 2018-19 के अप्रैल-दिसम्बर में निवल पूंजी प्रवाह पर्याप्त प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के बावजूद भी कम था जबकि पोर्ट फोलियों निवेश के अंतर्गत आहरण इससे ज्यादा था।
- विदेशों में काम कर रहे भारतीयों द्वारा निवल विप्रेषण 2018-19 (अ) में पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है, यह संभवतः खाड़ी देशों में उच्च आय की दशाओं तथा तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण था। वर्ष 2018 में भारत शीर्ष विप्रेषण प्राप्तकर्ता देश बना रहा है।
- चालू खाताघारक वाली मुख्य अर्थव्यवस्था में, भारत के पास सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार है और विश्व के सभी देशों में इसका आठवाँ स्थान है।
- दिसंबर 2018 के अंत में, भारत का विदेशी ऋण 521.1 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो मार्च, 2018 के अंत के इस स्तर से 1.6 प्रतिशत कम था। विदेशी ऋण के मुख्य संकेतक यह दर्शाते हैं कि भारत का विदेशी ऋण असतत नहीं है।
- कुल देनदारियों एवं जीडीपी का अनुपात, ऋण और गैर ऋण घटक दोनों को मिलाकर, 2015 के 43 प्रतिशत से घटकर 2018 में लगभग 38 प्रतिशत मापी जा रही है। कुल देनदारियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का हिस्सा बढ़ा है जबकि निवल पोर्टफोलियो निवेश का हिस्सा घटा है जो कि चालू खाता घाटा वित्त पोषण के बढ़ते स्थायी साधनों के स्वरूप को प्रदर्शित कर रहा है।
- भारतीय रुपये ने 2017-18 में 65-68 प्रति अमरीकी डालर के बीच में कारोबार किया था परंतु 2018-19 में यह 70-74 के बीच तक गिर गया था। 2018-19 की पहली छमाही में, यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा फेडरल निधियों की दर में वृद्धि किए जाने से वित्तीय परिस्थितियों में संकुचन के साथ कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण चालू खाता घाटा बढ़ने से रुपया कमजोर बना रहा।

- व्यापार के संबंध में आय, एक मापक जो कि आयात की क्रय शक्ति मापती है, आरोही प्रवृत्ति पर रही, संभवतः इसलिए क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों की वृद्धि भारत की निर्यात कीमतों से अभी तक अधिक नहीं हो पाई थी। वर्ष 2018-19 में विनियम दर पिछले वर्ष की तुलना में अधिक अस्थिर रही जिसका मुख्य कारण कच्चे तेल के मूल्यों में उतार-चढ़ाव रहा, न कि यह उतार-चढ़ाव निवल पोर्टफोलियो प्रवाहों के कारण रहा।
  - भारत की आयात एवं निर्यात टोकरी का संघटन 2017-18 की अपेक्षा 2018-19 में कमोवेश अपरिवर्तित बना रहा। पेट्रोलियम पदार्थों, बहुमूल्य रत्न, सूत्र विन्यासित औषधियां, सोने एवं अन्य बहुमूल्य धातुएं शीर्ष निर्यात वस्तुएं बनीं रही हैं। कच्चा पेट्रोल तेल, मोती, बहुमूल्य, अर्धबहुमूल्य पत्थर तथा सोना शीर्ष आयात वस्तु बनी रही। भारत के मुख्य व्यापार भागीदार अमरीका, चीन, हांगकांग, यूई तथा सऊदी अरब बने रहे।
  - भारत ने विभिन्न देशों/देशों के समूह के साथ 28 द्विपक्षीय/बहुपक्षीय कारोबार करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। 2018-19 में भारत का ऐसे देशों के साथ निर्यात जिनके साथ इसका कारोबार करार है, 121.7 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जो सभी देशों को भारत के निर्यात का 36.9 प्रतिशत बैठता है। इसी प्रकार, समान वर्ष में, भारत का ऐसे देशों से आयात जिनके साथ इसका कारोबार करार है 266.9 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा जो भारत का सभी देशों से आयात का 52.0 प्रतिशत बैठता है।
  - भारत का संभारतंत्र उद्योग वर्तमान में लगभग 215 बिलियन अमरीकी डॉलर के आसपास होने का अनुमान है। इस उद्योग में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के चलते विश्व बैंक के 2016 संभारतंत्र निष्पादन सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग के अनुसार, समग्र संभारतंत्र निष्पादन में भारत की रैंकिंग में उछाल आया है। वर्ष 2018 में, भारत का 44वाँ स्थान रहा।
-



के नए अभिप्रेरक बनते हैं और सीएडी का बिगड़ना वृहत आर्थिक परिप्रेक्ष्य से रोका जा सकता है।

## अनुबंध I

### I. वस्तु व्यापार

\* पिछले दस वर्षों में वस्तु निर्यात, आयात और व्यापार संतुलन में बड़े रुझान नीचे सारणी में दर्शाए गए हैं:—

#### सारणी 1: वस्तु व्यापार

मूल्य बिलियन अमरीकी डालर में

क्रम सं.	वर्ष	निर्यात	वृद्धि ( : )	आयात	वृद्धि ( : )	व्यापार संतुलन
1	2009-10	178.75	-3.53	288.37	-5.05	-109.62
2	2010-11	249.82	39.76	369.77	28.23	-119.95
3	2011-12	305.96	22.48	489.32	32.33	-183.36
4	2012-13	300.40	-1.82	490.74	0.29	-190.34
5	2013-14	314.41	4.66	450.20	-8.26	-135.80
6	2014-15	310.34	-1.29	448.03	-0.48	-137.70
7	2015-16	262.29	-15.48	381.01	-14.96	-118.72
8	2016-17	275.85	5.17	384.36	0.88	-108.51
9	2017-18	303.53	10.03	465.58	21.13	-162.06
10	2018-19 (QE)	330.07	8.75	514.03	10.41	-183.96

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता

टिप्पणी: क्यूई का तात्पर्य शीघ्र अनुमान है।

### II. भारत का सेवा व्यापार

#### सारणी 2: सेवा व्यापार

मूल्य बिलियन अमरीकी डालर में

क्रम सं.	वर्ष	निर्यात	वृद्धि ( % )	आयात	वृद्धि ( % )	निवल सेवाएं
1	2009-10	96.04	-9.36	60.03	15.34	36.02
2	2010-11	124.64	29.77	80.55	34.19	44.08
3	2011-12	142.32	14.19	78.23	-2.89	64.10
4	2012-13	145.68	2.36	80.76	3.24	64.91
5	2013-14	151.81	4.21	78.75	-2.50	73.07
6	2014-15	158.11	4.15	81.58	3.59	76.53
7	2015-16	154.31	-2.40	84.63	3.75	69.68
8	2016-17	164.20	6.41	95.85	13.25	68.34
9	2017-18	195.09	18.81	117.53	22.61	77.56
10	2018-19 (P)*	205.79	5.49	125.46	6.75	80.33

स्रोत: आरबीआई डाटाबेस और प्रैस विज्ञप्तियां, टिप्पणी पी का तात्पर्य अनंतिम है।

\*टिप्पणी 2:- सेवा संबंधी आंकड़े मार्च 2019 से संबंधित हैं क्योंकि दिनांक 15 मई, 2019 की आरबीआई की प्रैस विज्ञप्ति के अनुसार ये नवीनतम उपलब्ध आंकड़े हैं। 2018-19 के आंकड़े जनवरी, फरवरी और मार्च 2018-19 के लिए आरबीआई की प्रैस विज्ञप्ति के महीनेवार क्यूई आंकड़ों के साथ 2018-19 की पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही के लिए आरबीआई के तिमाही आंकड़ों को जोड़कर प्राप्त किए गए हैं। ये आंकड़े अनंतिम हैं और आरबीआई के संशोधन के अध्वधीन हैं।



यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि निवल सेवाएं 2018-19 (व्यूई) में वस्तु व्यापार घाटे का 43.67% वित्तपोषण कर रही है।

## अनुबंध- II

## सारणी 3: भुगतान संतुलन ( मिलियन अमरीकी डालर )

क्रम संख्या	मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2017-18	2018-19
							Apr-Dec	Apr-Dec P
1	2	3	4	5	6	7	9	8
I	चालू खाता							
1	निर्यात	3,18,607	3,16,545	2,66,365	2,80,138	3,08,970	2,26,753	2,49,869
2	आयात	4,66,216	4,61,484	3,96,444	3,92,580	4,69,006	3,45,166	3,95,142
3	व्यापार शेष (1.2)	-1,47,609	-1,44,940	-1,30,079	-1,12,442	-1,60,036	-1,18,413	-1,45,272
4	अदृश्य (निवल)	1,15,313	1,18,081	1,07,928	98,026	1,11,319	82,762	93,407
	A. सेवाएं	73,066	76,529	69,676	68,345	77,562	57,398	60,254
	B. आय	-23,028	-24,140	-24,375	-26,302	-28,681	-20,861	-20,452
	C. अंतरण	65,276	65,692	62,627	55,983	62,438	46,225	53,605
5	माल एवं सेवा शेष	-74,544	-68,411	-60,402	-44,098	-82,474	-61,015	-85,019
6	चालू खाता शेष (3+4)	-32,296	-26,859	-22,151	-14,417	-48,717	-35,651	-51,865
II	पूँजी खाता							
	पूँजी खाता शेष	48,787	89,286	41,128	36,447	91,390	66,366	35,275
	i. विदेशी सहायता (निवल)	1,032	1,725	1,505	2,013	2,944	1,514	2,160
	ii. विदेशी वाणिज्यिक उधार (निवल)	11,777	1,570	-4,529	-6,102	-183	-1,175	2,785
	iii. लघु अर्वाधि ऋण	-5,044	-111	-1,610	6,467	13,900	9,357	553
	iv. बैंकिंग पूँजी (निवल)							
	जिसका गैर प्रनिवासी जमा (निवल)	25,449	11,618	10,630	-16,616	16,190	11,561	15,496
	जिसका गैर प्रनिवासी जमा (निवल)	38,892	14,057	16,052	-12,367	9,676	5,040	6,977
	v. विदेशी निवेश (निवल)							
	जिसका	26,386	73,456	31,891	43,224	52,401	43,718	14,766
	A. फडीआई							
	पोर्टफोलियो (निवल)	21,564	31,251	36,021	35,612	30,286	23,879	24,820
	B. अन्य प्रवाह (निवल)	4,822	42,205	-4,130	7,612	22,115	19,839	-10,054
	vi. अन्य प्रवाह (निवल)	-10,813	1,028	3,242	7,460	6,138	1,393	-485
III	भूल-चूक लेनी देनी	-983	-1,021	-1,073	-480	902	-378	-912
IV	समग्र शेष	15,508	61,406	17,905	21,550	43,574	30,338	17,502
V	भंडार बदलाव	-15,508	-61,406	-17,905	-21,550	-43,574	-30,338	17,502
	बढ़ोत्तरी (+) कमी (-)							

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

सारणी 4: विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन का सार( बिलियन अमरीकी डालर )

क्र. सं.	वर्ष	वित्तीय वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार	भंडार में कुल बढ़ोत्तरी कमी	बीओपी आधार पर भंडारों में बढ़ोत्तरी (+) कमी	मूल्यांकन (+) प्रभाव (-) के कारण भंडार में लाभ/हानि
1	2007-08	309.7	110.5	92.2	18.3
1	2008-09	252.0	-57.7	-20.1	-37.6
2	2009-10	279.1	27.1	13.4	13.7
3	2010-11	304.8	25.8	13.1	12.7
4	2011-12	294.4	-10.4	-12.8	2.4
5	2012-13	292.0	-2.4	3.8	-6.2
6	2013-14	304.2	12.2	15.5	-3.3
7	2014-15	341.6	37.4	61.4	-24.0
8	2015-16	360.2	18.5	17.9	0.6
9	2016-17	370.0	9.8	21.6	-11.8
10	2017-18	424.5	54.6	43.6	11.0
1	अप्रैल-दिसम्बर 2017-18	409.1	39.1	30.3	8.8
2	अप्रैल-दिसम्बर 2018-19	395.6	-29.0	-17.5	-11.5

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)

सारणी 5: 2018-19 के दौरान प्रति विदेशी मुद्रा की विनिमय दर तथा विनिमय बाजार में अमरीकी डालर की भारतीय रिजर्व बैंक की बिक्री/खरीद

औसत विनिमय दर (प्रति विदेशी मुद्रा रू.)

माह	अमरीकी डालर	पाऊंड टर्लिंग	यूरो	जापानी येन	आरबीआई निवल	
					बिक्री	खरीद (बिलियन अमरीकी डालर)
1	2	3	4	5	6	
2016-17	67.07	87.69	73.61	62.04	12351	
	(-2.4)	(12.6)	(-1.8)	(-12.0)		
2017-18	64.45	85.51	75.44	58.18	33689	
	(4.1)	(2.5)	(-2.4)	(6.6)		
2018-19	69.92	91.79	80.96	63.05	-15377	
	(-7.8)	(-6.8)	(-6.8)	(-7.7)		
मासिक औसत						
Apr-18	65.64	92.57	80.66	61.02	-2483	
	(-0.9)	(-1.9)	(-0.5)	(0.5)		
May-18	67.54	90.97	79.82	61.55	-5767	
	(-2.8)	(1.8)	(1.0)	(-0.9)		
Jun-18	67.79	90.07	79.16	61.61	-6184	
	(-0.4)	(1.0)	(0.8)	(-0.1)		
Jul-18	68.69	90.50	80.30	61.66	-1874	
	(-1.3)	(-0.5)	(-1.4)	(-0.1)		
Aug-18	69.55	89.69	80.44	62.59	-2323	
	(-1.2)	(0.9)	(-0.2)	(-1.5)		
Sep-18	72.22	94.19	84.22	64.50	-31	
	(-3.7)	(-4.8)	(-4.5)	(-3.0)		
Oct-18	73.63	95.87	84.61	65.27	-7204	
	(-1.9)	(-1.8)	(-0.5)	(-1.2)		
Nov-18	71.85	92.62	81.62	63.37	-644	
	(2.5)	(3.5)	(3.7)	(3.0)		
Dec-18	70.73	89.58	80.48	62.96	607	
	(1.6)	(3.4)	(1.4)	(0.7)		
Jan-19	70.73	91.16	80.83	64.96	293	
	(0.0)	(-1.7)	(-0.4)	(-3.1)		
Feb-19	71.22	92.67	80.85	64.55	825	
	(-0.7)	(-1.6)	(0.0)	(0.6)		
Mar-19	69.48	91.55	78.51	62.51	9048	
	(2.5)	(1.2)	(3.0)	(3.3)		

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

टिप्पणी: 100 येन प्रति रू

कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशत में पिछले महीने/वर्ष की अपेक्षा वृद्धि(+) तथा ह्रास(-) दर्शाता है।

पूर्णांकित करने के कारण आंकड़े मिलाए नहीं जा सकते।

डालर की निवल बिक्री एवं खरीद के आंकड़े सितंबर 2017 तक उपलब्ध हैं।

## सारणी 6: भारतीय रुपये का एनईईआर एवं आरईईआर ( सीपीआई आधारित ) की सूचियां

( छ: मुद्रा व्यापार आधारित भार )

आधार वर्ष: 2004-2005 ( अप्रैल-मार्च )=100

मासिक औसत	एनईईआर	पिछली अवधि महीने की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (-)	आरईईआर	पिछली अवधि महीने की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (-)
1	2	3	4	5
2016-17	66.86	-1.0	125.17	2.0
2017-18	67.91	1.6	121.19	3.2
2018-19	63.07	-7.1	121.70	-5.8
2018-19 (P)				
अप्रैल 2018	64.53	-0.9	123.47	-0.8
मई 2018	63.84	-1.1	123.06	-0.3
जून 2018	64.1	0.4	123.18	0.1
जुलाई 2018	64.03	-0.1	123.37	0.2
अगस्त 2018	63.84	-0.3	123.63	0.2
सितंबर 2018	61.35	-3.9	118.69	-4.0
अक्तूबर 2018	60.64	-1.2	117.29	-1.2
नवंबर 2018	62.4	2.9	121.25	3.4
दिसंबर 2018	63.23	1.3	122.74	1.2
जनवरी 2019	62.76	-0.7	120.67	-1.7
फरवरी 2019	62.29	-0.7	119.72	-0.8
मार्च 2019	63.88	2.5	123.3	3.0

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

## I- 2017-18 में शीर्ष दस वस्तुओं का निर्यात

मूल्य बिलियन अमरीकी डालर में

रैंक	वस्तु	2016-17	2017-18	%वृद्धि	%शेयर
1.	पेट्रोलियम उत्पाद	31.55	37.47	18.77	12.34
2.	मोती, मूल्यवान, अर्ध मूल्यवान पत्थर	24.92	25.87	3.8	8.52
3.	ड्रग फार्मूलेशन, जैविक पदार्थ	12.67	12.91	1.92	4.25
4.	स्वर्ण और अन्य मूल्यवान धातु के आभूषण	11.93	12.81	7.31	4.22
5.	लौह और इस्पात	8.68	11.24	29.5	3.7
6.	एक्सेसरीज सहित आरएमजी कॉटन	8.51	8.51	-0.03	2.8
7.	मोटर वाहन/कार	7.55	8.47	12.26	2.79
8.	समुद्री उत्पाद	5.90	7.39	25.18	2.43
9.	जैविक रसायन	4.84	7.14	47.44	2.35
10.	लौह और इस्पात के उत्पाद	5.90	6.77	14.84	2.23

स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता।

## II- 2018-19 में शीर्ष दस वस्तुओं का निर्यात

मूल्य बिलियन अमरीकी डालर में

रैंक	वस्तु	2016-17	2017-18	%वृद्धि	%शेयर
1.	पेट्रोलियम उत्पाद	37.47	46.54	24.23	14.10
2.	मोती, मूल्यवान, अर्ध मूल्यवान पत्थर	25.87	25.98	0.43	7.87
3.	ड्रग फार्मूलेशन, जैविक पदार्थ	12.91	14.39	11.46	4.36
4.	स्वर्ण और अन्य मूल्यवान धातु के आभूषण	12.81	12.94	1.02	3.92
5.	लौह और इस्पात	11.24	9.74	-13.36	2.95
6.	जैविक रसायन	7.14	9.33	30.58	2.83
7.	एक्सेसरीज सहित आरएमजी कॉटन	8.51	8.69	2.16	2.63
8.	मोटर वाहन/कार	8.47	8.50	0.32	2.58
9.	बिजली की मशीनरी और उपस्कर	6.71	8.42	25.68	2.55
10.	लौह और इस्पात के उत्पाद	6.77	7.26	7.22	2.2

स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता।

## अनुबंध VI ( जारी )

## III- 2017-18 में शीर्ष दस वस्तुओं का आयात

मूल्य बिलियन अमरीकी डालर में

रैंक	वस्तु	2016-17	2017-18	%वृद्धि	%शेयर
1.	पेट्रोलियम : कच्चा	70.71	87.37	23.57	18.77
2.	मोती, मूल्यवान, अर्ध मूल्यवान पत्थर	23.81	34.28	43.98	7.36
3.	स्वर्ण	27.52	33.66	22.31	7.23
4.	कोयला, कोक और बिक्रेट आदि	15.76	22.90	45.31	4.92
5.	दूरसंचार के उपकरण	16.57	21.85	31.84	4.69
6.	पेट्रोलियम उत्पाद	16.26	21.29	30.93	4.57
7.	जैविक रसायन	9.88	12.43	25.81	2.67
8.	वनस्पति तेल	10.89	11.64	6.84	2.5
9.	प्लास्टिक की कच्ची सामग्री	8.81	10.69	21.34	2.3
10.	डेरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी	9.38	10.48	11.8	2.25

स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता।

## IV 2018-19 में शीर्ष दस वस्तुओं का आयात

मूल्य बिलियन अमरीकी डालर में

रैंक	वस्तु	2016-17	2017-18	%वृद्धि	%शेयर
1.	पेट्रोलियम : कच्चा	87.37	114.04	30.52	22.19
2.	स्वर्ण	33.66	32.90	-2.26	6.40
3.	मोती, मूल्यवान, अर्ध मूल्यवान पत्थर	34.28	27.08	-21.01	5.27
4.	पेट्रोलियम उत्पाद	21.29	26.88	21.26	5.23
5.	कोयला, कोक और बिक्रेट आदि	22.90	26.17	14.28	5.09
6.	दूरसंचार के उपकरण	21.85	17.92	-17.99	3.06
7.	इलेक्ट्रॉनिक घटक	10.18	15.75	54.63	2.77
8.	जैविक रसायन	12.43	14.25	14.66	2.78
9.	लौह और इस्पात	10.43	12.58	20.60	2.45
10.	डेरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी	10.48	12.47	18.97	2.43

स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता।

## अनुबंध VII

## I- 2017-18 में भारत के दस शीर्ष निर्यात स्थल

मूल्य बिलियन अमरीकी डालर में

पद क्रम	देश	2016-17	2017-18	%वृद्धि	%शेयर
1.	संरा० अमेरिका	42.22	47.88	13.42	15.78
2.	संयुक्त अरब अमीरात	31.18	28.15	-9.72	9.27
3.	हांककांग	14.05	14.69	4.58	4.84
4.	चीन	10.17	13.33	31.08	4.39
5.	सिंगापूर	9.56	10.20	6.67	3.36
6.	यू०के०	8.55	9.71	13.58	3.2
7.	जर्मनी	7.18	8.69	20.96	2.86
8.	बांग्लादेश	6.82	8.61	26.31	2.84
9.	वियतनाम	6.79	7.81	15.13	2.57
10.	नेपाल	5.45	6.61	21.26	2.18

स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता।

## II- 2018-19 (अ) में भारत के दस शीर्ष निर्यात स्थल

मूल्य बिलियन अमरीकी डालर में

पद क्रम	देश	2017-18	2018-19 (अ)	%वृद्धि	%शेयर
1.	संरा० अमेरिका	47.88	52.42	9.48	15.91
2.	संयुक्त अरब अमीरात	28.15	30.09	6.9	9.13
3.	चीन	13.33	16.75	25.62	5.08
4.	हांककांग	14.69	12.96	-11.76	3.93
5.	सिंगापूर	10.20	11.57	13.39	3.51
6.	यू०के०	9.71	9.33	-3.91	2.83
7.	बांग्लादेश	8.61	8.93	3.7	2.71
8.	जर्मनी	8.69	8.90	2.48	2.7
9.	नीदरलैंड	6.26	8.81	40.73	2.67
10.	नेपाल	6.61	7.62	15.17	2.31

स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता।

## III- 2017-18 में भारत के दस शीर्ष आयात स्थल

मूल्य बिलियन अमरीकी डालर में

पद क्रम	देश	2016-17	2017-18 (अ)	%वृद्धि	%शेयर
1	चीन	61.28	76.38	24.64	16.41
2	संरा० अमेरिका	22.31	26.61	19.29	5.72
3	सउदी अरब	19.97	22.07	10.5	4.74
4	संयुक्त अरब अमीरात	21.51	21.74	1.07	4.67
5	स्वीटजरलैंड	17.25	18.92	9.71	4.06
6	ईराक	11.71	17.62	50.46	3.78
7	इंडोनेशिया	13.43	16.44	22.42	3.53
8	कोरिया	12.59	16.36	30.01	3.51
9	ऑस्ट्रेलिया	11.15	13.99	25.45	3.01
10	जर्मनी	11.58	13.30	14.78	2.86

स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता।

## IV- 2018-19 में भारत के दस शीर्ष आयात स्थल

मूल्य बिलियन अमरीकी डालर में

पद क्रम	देश	2017-18	2018-19 (अ)	%वृद्धि	%शेयर
1	चीन	76.38	70.32	-7.94	13.68
2	संरा० अमेरिका	26.61	35.55	33.59	6.92
3	संयुक्त अरब अमीरात	21.74	29.78	37.01	5.79
4	सउदी अरब	22.07	28.48	29.04	5.54
5	ईराक	17.62	22.37	27.00	4.35
6	स्वीटजरलैंड	18.92	18.08	-4.47	3.52
7	हांगकांग	10.68	17.99	68.48	3.50
8	कोरिया	16.36	16.76	2.43	3.26
9	सिंगापुर	7.47	16.28	118.05	3.17
10	इंडोनेशिया	16.44	15.85	-3.59	3.08

स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता।



## द्विपक्षीय व्यापार प्रबंधों की प्रगति

क्र.सं.	प्रादेशिक समूह	देश	करार नाम	मुख्य विशेषताएं
1.	यूरोप	ई यू देश	भारत-ईयू बीटीआईए वार्ताचरण	वर्ष 2007 में शुरू हुई। 2013 तक वार्ता के 16 दौर हो चुके हैं।
		स्विट्जरलैंड, आइसलैंड तथा लिचेंस्टीन	यूरोपीय मुक्त व्यापार समिति	2018-19 के दौरान 19.9 बिलियन अमीकी डालर का कुल द्विपक्षीय व्यापार
		स्विट्जरलैंड, आइसलैंड तथा लिचेंस्टीन	भारत-ईएफटीए टीईपीए (वार्ता चरण)	व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए) अक्टूबर, 2008 में शुरू हुआ वार्ता के 17 दौर हो चुके हैं। वार्ता का अंतिम दौर 18-21 सितंबर, 2017 को हुआ था।
2-	साक	बांग्लादेश	द्विपक्षीय व्यापार करार	स्वचालित नवीकरण खंड सहित 1 अप्रैल, 2015 से 5 वर्षों हेतु नवीकृत किया गया। उत्पादों के आयात हेतु कोई अधिमान्य प्रशुल्क नहीं, केवल सुविधातंत्र व्यापार/आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) में प्रवेश हेतु संभावनाओं का पता लगाना।
		ईरान	अधिमान्य व्यापार करार (पीटीए) (वार्ता चरण)	2013 में शुरू हुई। वार्ता के चार दौर हो चुके हैं। अगला दौर जून, 2019 में भारत में अस्थायी रूप से होना निर्धारित है।
		नेपाल	भारत-नेपाल व्यापार संधि	27 अक्टूबर, 2016 को आखिरी बार नवीकृत किया गया। शुल्क मुक्त प्रवेश उपलब्ध कराया गया। संधि की व्यापक समीक्षा शुरू हुई तथा अगस्त, 2018 में दो बैठकें हुईं। और फरवरी, 2019
		श्रीलंका	भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता (आईएसएल एफटीए)	2000 में लागू हुआ प्रशुल्क में छूट दी गई। भारत ने कुछ को छोड़कर लगभग सभी को शुल्क मुक्त प्रवेश प्रदान किया।
		श्रीलंका	व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए)	वार्ता 2008 में संपूर्ण। किंतु समझौते को प्रभावी नहीं किया जा सका।
		श्रीलंका	आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता (ईटीसीए) (वार्ता चरण)	द्विपक्षीय बैठक 2015 में शुरू हुई। अक्टूबर, 2018 तक 11 दौर में बातचीत हुई।

3-	आसियान	भारत, मलेशिया, सिंगापुर तथा थाइलैंड	आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता (एआईटीआरजीए)	1 जनवरी, 2010 को लागू हुआ। सभी आसियान सदस्य एफटीए के हस्ताक्षरकर्ता हैं। एआईओआईजीए की समीक्षा रोकी गई है जब तक आरसीईपी की बातचीत के निष्कर्ष प्राप्त नहीं होते।
		सिंगापुर	भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए)	29 जून, 2005 को हस्ताक्षर किए गए इसमें वस्तुएं, सेवाएं तथा निवेश शामिल हैं। पहली समीक्षा 2006 में हुई। दूसरी समीक्षा 2010 में हुई।
		सिंगापुर	सिंगापुर के साथ नर्सिंग क्षेत्र में परस्पर मान्यता सहमति पत्र	सिंगापुर भारत के सात नर्सिंग संस्थाओं को मान्यता प्रदान करके भारतीय नर्सिंग संस्थाओं के विस्तार के लिए सहमति प्रदान की।
		थाइलैंड	भारत-थाइलैंड सीईसीए	2004 में लागू हुआ। प्रशुल्क में कमी तथा चरणबद्ध तरीके से अलग करने हेतु 84 उत्पादों को शामिल करते हुए शीघ्र कटाई योजना कटाई योजना को कार्यान्वित करने हेतु सहमति प्रदान की। थाइलैंड के साथ व्यापक एफटीए हेतु वार्ता में 30 दौर हुए।
4.	दक्षिणी अमेरिका	अर्जेन्टीना, ब्राजील, पैराग्वे, और उरुग्वे	भारत-एमईआर सीओएजयूआर अधिमान व्यापार करार	1.7.2011 से लागू हुआ। आईएमसीईसीए के अनुपालन हेतु संयुक्त समिति की पहली बैठक 2014 में हुई।
		चिली	भारत-चिली वरीयता अधिमान्य व्यापार (पी.टी.ए)	2009 में शुरू हुआ वरीयता अंतराल टैरिफ लाइन पर प्रस्तुत किया गया है।
		पेरू	भारत-पेरू व्यापार करार (वार्ता चरण)	2007 में प्रभावी। वरियता की अतिरिक्त राशि (एम.ओ.पी.) टैरिफ श्रृंखला पर प्रदान किये जाते हैं।
		इक्वेडोर	भारत-इक्वेडोर व्यापार करार (वार्ताचरण)	वार्ता के चार दौर हो चुके हैं पिछली वार्ता मार्च, 2019 में हुई। अगली वार्ता अगस्त, 2019 में प्रस्तावित है।
		कोलंबिया	भारत-कोलंबिया व्यापार करार (वार्ताचरण)	व्यापार करार की संभावनाएं खोजना
		कोलंबिया	भारत-कोलंबिया व्यापार करार (वार्ताचरण)	व्यापार करार की संभावनाएं खोजना
5.	राष्ट्रमंडल स्वतंत्र देश (सीआईएस)	पी टी ए के साथ यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन (ईईईयू) (वार्ता चरण)	यूरोशियन इकनॉमिक यूनियन के साथ पीटीए हेतु बातचीत शुरू की।	
		जार्जिया	जार्जिया के साथ एफटीए (वार्ता चरण)	जार्जिया के साथ एफटीए की शुरूआत

	उजबेकिस्तान	उजबेकिस्तान के साथ जेएफएसजी (वार्ता चरण)	उजबेकिस्तान के साथ जेएफएसजी की शुरूआत हेतु संयुक्त पत्रक पर हस्ताक्षर किए।
6.	अफ्रीका-डब्ल्यू ए एन ए (पश्चिमी एशिया उत्तरी अफ्रीका)	भारत-मॉरीशस व्यापार आर्थिक सहयोग तथा साझेदारी करार (सीईसीपीए)(वार्ताचरण)	वार्ता के 7 दौर हो चुके हैं।
	इजराइल	भारत-इजराइल एफटीए (वार्ता चरण)	
	बोत्सवाना, लेसोथो, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और एसवातिनी 15 देशों का समूह नामतः बेनिन, बर्किना फासो, केबो वर्डे, कोटडी, जांबिया, गिनीया, बिसाऊ, लाइबीरिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया से ने गल, सियारा लेयोन और टोगो	भारत-एसएसीसीपीटीए (वार्ता चरण)	दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क यूनियन (एसएसीयू) 2010 में छठा दौर।
7.	उत्तरी अमेरिका	भारत-ईसीओ डब्ल्यूएसीपीटीए (वार्ता चरण)	
	उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता (एनएफटीए)	उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता (एनएफटीए)	भारत-अमरीका वाणिज्यिक वार्तालाप पर 2000 में हस्ताक्षर
	संयुक्त राज्य अमेरिका		भारत-अमरीका व्यापार नीति फोरम की 2005 में घोषणा हुई-व्यापार मामलों का समाधान करने के लिए संस्थागत तंत्र का निर्माण करने में सहायक।
	कनाडा		भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक नीति समझौता (सीईपीए): 2010 में शुरू किया गया, अब तक वार्ता के 10 दौर हो चुके हैं।
8.	ओशिनिया	आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एफटीए	आस्ट्रेलिया से बातचीत के 9 दौर न्यूजीलैंड से बातचीत के 10 दौर हो चुके हैं।